Kolkata and Chennai, and, had shifted the entire management procedures involving Continuous Discharge Certificates of the Indian seafarers from Kolkata and Chennai to Mumbai.

These decisions to centralize dealings have become a cause of miserable inconvenience for the seafarers in general. They are all being compelled to travel to Mumbai from the far away points, from the Eastern and Southern region to the West Coast for their CDC related work. Furthermore, posts of Shipping Masters are lying vacant and the whole workload has been handled by the clerical category, which does not have the requisite authority to deal with all sorts of situations, which may be the cause to any untoward incident.

I, therefore, request the hon. Minister of Shipping to revert the decision and return to the previously existing system. I also urge upon the Government to fill the vacant Shipping Masters posts immediately.

SHRI SAMAN PATHAK (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

---

## GOVERNMENT BILL

### The Gram Nyayalayas Bill, 2008

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up further discussion on the Gram Nyayalayas Bill, 2008. Mr. Ahluwalia to continue.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, yesterday, I initiated the discussion on the Gram Nyayalayas Bill, and, when the House was adjourned, I was talking about the essence of Kautilya's jurisprudence, and, how we switched over from Kautilya's jurisprudence to criminal jurisprudence of Britain. After so many years after achieving freedom, we are now thinking about providing justice at the doorstep or at the door of villages, which was the real essence of Kautilya's jurisprudence. We were having all these things with us. But, all the good values were taken over by the Westerns and we followed that for 60 long years. For this commendable Bill also, which is a revolutionary step, the 114th Report of the Law Commission which suggested a Gram Nyayalaya was pending in the Law Ministry since 1986. Many Governments came and gone in between. Now, ultimately, you have brought this Bill. If you see the history of this long journey from 1986 till today, initially the Bill was drafted in 2005. That 2005 Bill was referred to the National Advisory Council which was functioning under the Prime Minister's Office. At that time a tug of war started whether Nyaya Panchayat or Gram Nyayalaya should come. I remember and I just want to refresh the memories of the Members of this House, especially the learned hon. Minister that on 18th December 2005, Law Ministers Conference endorsed village courts. At that time, he said, "Goal was to take justice to the doorstep of all those in the countryside, who cannot afford litigation for which they have to travel long distances and spend heavily". But, simultaneously, on 23rd August, 2006, Mani Shankar Aiyar, another Cabinet Minister of this Government, while replying in Lok Sabha, said, "A proposal to set up Nyaya Panchayats to

delegate more judicial rights to the grassroots in the country is under consideration. A Drafting Committee has been set up to draft a Bill. The objective of the proposed Nyaya Bill is to provide a sound alternative forum at the grassroots level for dispute resolution through mediation, conciliation and compromise which can be institutionalised with community involvement". It reminds me of the famous saying of Abraham Lincoln, "Discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can. Point out to them how a nominal winner is often a real loser in fees, expenses and waste of time". And, that is the reason the American Constitution provides in their fundamental right that everybody has the right not only to fair trial but also to speedy trial. When we discuss all these things, and specially when we discuss the 114th Report, Sir, the Commission submitted its Report and recommended about a Gram Nyayalaya in respect of disputes covered by the subject matters covered mentioned herein. Civil Disputes: Disputes arising out of implementation of agrarian reforms and allied statutes: Tenancies protected and concealed and contested; boundary disputes and encroachment; right to purchase; use of common pasture; entries in revenue records; regulation and timing of taking water from irrigation channel; disputes as to assessment. Then there are property disputes. These consist of village and farm houses; sobas; easements: right of way for man, cart and cattle to fields and courtyards; water channels; and right to draw water from a well or tubewell.

Then there are family disputes. These consist of marriage; divorce; custody of children; inheritance and succession and share in property; and maintenance.

Then there are other disputes. They are: non-payment of wages and violation of Minimum Wages Act; money suits either arising from trade transaction or money lending; disputes arising out of partnership in cultivation of land; disputes as to use of forest produce by local inhabitants; complaints of harassment against local officials belonging to police, revenue, forest, medical and transport departments; disputes arising under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976; and the Protection of Civil Rights Act, 1955.

The Gram Nyayalaya must have jurisdiction to try all offences which can be tried under the Code of Criminal Procedure, 1973, by the Judicial Magistrate First Class.

As I narrated yesterday, Sir, that the Gram Nyayalaya would be a body for administration of justice and a legislation for the same would squarely fall under Entry 11-A of the Concurrent List. It was decided that all the cases would be transferred, I mean, such cases which fall under this category would be transferred from the district court or mofussil court to the Gram Nyayalaya. And new cases in such category will be registered in these Gram Nyayalayas.

**श्री नन्द किशोर यादव** (उत्तर प्रदेश): सर, इस विधेयक के खंड 29 में यह कहा गया है कि, "यह खंड ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में राज्य की राजभाषा के प्रयोग के लिए उपबंध करने के लिए है। यह खंड उपबंध करता है कि ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां और उसका निर्णय जहां तक व्यवहार्य हो, अंग्रेजी भाषा में भिन्न राज्य की राज भाषाओं में से किसी एक में होगा।"

महोदय, अहलुवालिया जी को अनेक भाषाएं आती हैं। उन्हें हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, साथ ही और भाषाएं भी आती हैं। महोदय, पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहस राजभाषा में हो।

**श्री वीरेन्द्र भाटिया** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी एग्री करता हूं।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: महोदय, मैं आज का भाषण हिंदी भाषा में ही करना चाहता था। कल जब मैं घर लौटा तो मुझे दूरदराज गांव के इलाके से एक व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि, "अहलुवालिया जी, आप तो हिंदी में बोल सकते हैं, पंजाबी में बोल सकते हैं, बंगाली में बोल सकते हैं और असमिया में भी बोल सकते हैं। आप अंग्रेजी के अलावा दूसरी किसी भाषा में बोलिए। आप वहां उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे British Jurisprudence को और फिर उन्हीं की भाषा में बोल रहे थे। यह उचित नहीं है, आप हिंदी में ही बोलो।" मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही बोलूं, पर मैं इसे देखूंगा। अब चूंकि मैंने तैयारी अंग्रेजी में की हुई थी, इसलिए मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। अब यादव जी ने इस बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं शुद्ध और अच्छी हिंदी में अपनी बात आपके सामने रखूं।

**श्री यशवंत सिन्हा** (झारखंड): आप हिंदी में अंग्रेजी बोलो।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: हिंग्रेजी?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी)**: आधी हिंदी, आधी अंग्रेजी बोलिए।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: महोदय, मैं कल बता रहा था कि यह बिल सब से पहले 114वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, जस्टिम सोहोनी कमेटी ने, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था, उसे कंसीडर किया और उसके बाद वहां वर्ष 1996 में वे मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम लेकर आए।

महोदय, मैंने अभी दो वक्तव्य पढ़कर सुनाए — एक हमारे विद्वान मित्र माननीय श्री हंसराज भारद्वाज जी का और दूसरा हमारे दूसरे विद्वान मित्र माननीय श्री मणि शंकर अय्यर जी का — जिनमें दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी है कि यह बिल ग्राम पंचायत में जाएगा या ग्राम न्यायालय में जाएगा या लोक अदालत में जाएगा। महोदय, मैं यहां बताना चाहूंगा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, जो lowest rung of the society या नीचे के स्तर पर चलता है, वह किस पद्धति से है। न्याय पंचायत, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। अब न्याय पंचायत कब से चल रहा है? From pre-independence. लोक अदालत, 1982 से और ग्राम न्यायालय, इस पर आज हम बहस कर रहे हैं। उसमें कौन-से अफसर होते हैं? तो न्याय पंचायत में, elected by local electroate, जो वहां से निर्वाचित होते हैं। लोक अदालत में, रिटायर्ड जजेज और वालेंटियर्स। ग्राम न्यायालय में, न्याय अधिकारी selected by High Court. नॉर्म्स कौन से एप्लाइ होते हैं? न्याय पंचायत में statute law है। लोक अदालत का कौन सा लॉ है, अभी तक किसी को नहीं मालूम है, लेकिन लोक अदालत काम करती हैं। अभी पीछे पढ़ा कि हरियाणा में एक दिन में ही लोक अदालत ने दो लाख केस खत्म कर दिए। ग्राम अदालत के लिए स्टेट लॉ और कनसोलेशन आएगा। मैक्सिमम पैनेल्टी फाइन्स हैं, न्याय पंचायत में और लोक अदालत में enforced by court और ग्राम न्यायालय में सजा है एक साल तक, या उसके साथ जो फाइन होगा, वह है। न्याय पंचायत की अपील भी कोर्ट में हो सकती है, लोक अदालत की अपील कहीं नहीं हो सकती और ग्राम न्यायालय की अपील सेसन जज के सामने या सीनियर सिविल जज के सामने की जा सकती है। न्याय पंचायत में वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी पैरवी खुद करते हैं, लोक अदालत में आप खुद भी कर सकते हैं और वकील भी कर सकते हैं, ग्राम न्यायालय में भी आप खुद भी लड़ सकते हैं और वकील भी रख सकते हैं। तो यह तो आपकी तीन पद्धतियां हैं, जो चल रही हैं, लेकिन मूल मंशा क्या है? मूल मंशा है कि किसी तरह से हम जब यह 114वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, तो 2006 तक करीब तीन करोड़ केसेस पूरे देश में पेंडिंग थे और यह एक बहुत बड़ा सिर-दर्द है सरकार के सामने और खासकर के विधि विभाग के सामने कि यह संख्या केसे कम की जाए। इसके लिए जब एनडीए की सरकार थी, तो उन्होंने फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला लिया। ये

फास्ट ट्रेक कोर्ट चलाई गई, जिसका टाइम खत्म हो गया, उसका वर्तमान सरकार ने वर्ष 2010 तक टाइम बढ़ाया और कुछ अनुदान भी दिया, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ राज्यों के उदाहरण को भी सामने रखें। अब जैसे गुजरात ने पेंडेंसी को क्लीयर करने के लिए क्या ढर्रा अपनाया? गुजरात ने उसी इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसी मेजिस्टेसी को लेकर, उन्हीं अधिकारियों को लेकर उन्होंने मोर्निंग और इवनिंग कोर्ट लगा दीं और यह मोर्निंग और इवनिंग कोर्ट लगाकर उन्होंने पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम किया। हम इसका उपयोग दूसरे राज्यों में भी कर सकते हैं। हमारे यहां गर्मी के दिनों में मोर्निंग कोर्ट चलते हैं और एक बजे के बाद सब लोग घर चले जाते हैं। इसी तरह से नॉर्मल सीजन, विंटर सीजन और मानसून सीजन, जो हमारा ड्यूरिंग द डे कोर्ट चलता है, सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक चलता है। अगर हम इसको मोर्निंग इवनिंग कर दें, तो वही इन्फ्रास्ट्रक्चर यूस हो सकता है।

उपसभापति महोदय, अभी इस विषय पर और भी मेरे वक्ता हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं और nitty-gritty पर नहीं जाता, लेकिन एक मुद्दे पर जरूर कहना चाहूंगा और मंत्री जी का ध्यान इस ओर चाहूंगा। इस बिल के चेप्टर 4 में प्रोसिजरल इन क्रिमिनल केसेस, सेक्शन 19, इस सेक्शन 19 में कहा गया है:—

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or sub-section (2) of section 262 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Gram Nyayalaya shall try the offences in a summary way in accordance with the procedure specified in Chapter XXI of the said Code and the provisions of sub-section (1) of section 262 and sections 263 to 265 of the said Code, shall, so far as may be, apply to such trial."

अब मैं यह सैक्शन पढ़कर बताना चाहता हूं कि 262 क्या कहता है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि पेज नम्बर 4 पर सैक्शन 14:—

"Where the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may, by notification, add to or omit any item in Part I or Part II of the First Schedule or Part II of the Second Schedule, as the case may be, and it shall be deemed to have been amended accordingly."

और सैक्शन 12 में उन्होंने उल्लेख किया है कि पार्ट वन, क्रिमिनल प्रोसिजर के तहत, वह फर्स्ट शेड्यूल क्या है और कौन-कौन से उसके अहाते में आएंगे और सेकंड शेड्यूल क्या है। मैं फर्स्ट शेड्यूल पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट शेड्यूल कहता है: First Schedule as per sections 12 and 14: OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE (45 OF 1860)

"offences not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding two years;"

अर्थात् मृत्यु दंड नहीं, लाइफ टर्म नहीं, उम्र कैद नहीं और जिसमें दो साल से ऊपर सजा होती है, वह इसमें नहीं लाई जाएगी। उसके दूसरे पार्ट में लिखा है

"theft, under section 379, section 380 or section 381 of the Indian Penal Code (45 of 1860), where the value of the property stolen does not exceed rupees twenty thousand;"

महोदय, मैं यहां पर 371 पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 371 क्या कहता है। Punishment for theft.

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज)**: 379

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: सॉरी, 379 उसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ आफेंस है, पनिशमेंट है 'imprisonment for three years or fine or both.' It is a cognisable offence; nonbailable. Section 380 — Theft in dwelling house.

1.00 p.m.

उसका क्लासिफिकेशन ऑफ आफेंस है "imprisonment for seven years and fine; cognisable offence, nonbailable, triable by a magistrate; non-compoundable also."

Section 381 — Theft by a clerk of a servant of property in possession of master.

"The punishment is seven years and fine; cognisable, nonbailable, triable by the magistrate."

यह है अब उसके बाद उसी में sections 411, 414, 454, 456, 504 और section 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड भी समरी ट्रायल के माध्यम से ट्राई किये जाएंगे। महोदय, उनकी सजा भी तीन वर्ष है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें नॉन-बेलेबल है। लेकिन आपने अपने इस कानून में लिखा — नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे केस नहीं लाएंगे। अगर आप ऐसे केस नहीं लाएंगे — आज तो आप इस बिल को पास कराने के लिए सिर्फ इन केसों को ला रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आपने उसकी व्याख्या के सामने लिख दिया है कि बीस हजार की चोरी होगी तो इतनी सजा होगी। जब बीस हजार की चोरी का उल्लेख चार्जशीट में होगा। मैं एक साधारण सी बात करता हूं कि यह ग्राम न्यायालय बिल है और हमारे देश में गांव अभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं।

**श्री हंसराज भारद्वाज** : आप क्या बात कर रहे हैं?

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** : आप मेरी बात सुन लें, चाहे आप कंसिडर मत करना। जो सच है, जो वस्तुस्थिति है, मैं वह बता रहा हूं।

**श्री हंसराज भारद्वाज** : इतना अच्छा बोल रहे थे, अब आप कहां जा रहे हैं!

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** : मैं जो बोल रहा हूं, मेरे को उसमें आपकी मदद चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, I just want to take the sense of the House. It is 1 o'clock. Shall we dispense with the lunch?

SHRI S.S. AHLUWALIA: We can continue after lunch.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Let Mr. Ahluwalia finish. Then you can adjourn the House for lunch.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I will continue after lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o' clock for lunch.

————————

2.00 p.m.

**The House then adjourned for lunch at one of the clock.**

**The House reassembled after lunch at two of the clock,**
**MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.**

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** : उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक के प्रोसीजर summary trial पर बोल रहा था और मैंने इसके पहले first schedule में जो सैक्शंस लाए गए हैं, उनके बारे में जान-बूझकर इसलिए उल्लेख किया था कि summary trial क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जिस सैक्शन 262 का उल्लेख, इस बिल के क्लाज़ 19 में किया गया है, इसमें जिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का उल्लेख किया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के बारे में सैक्शन 262 कहता है कि — Procedure for Summary Trials

— In trial under this Chapter the procedure specified in this Code for the trial of summon cases shall be allowed as hereinafter mentioned....". Only summon cases और जो सैक्शंस पहले शैड्यूल में लिखे गए हैं, ये सारे वारंट केस हैं, non-bailable हैं, cognizance वाले हैं और जिनकी सज़ा 3 साल से 7 साल तक है, उनको इसमें रखा गया है। महोदय, सैक्शन 262(2) यह कहता है कि — "No sentence of imprisonment for a term exceeding three months shall be passed in the case of any conviction under the Chapter". इसका मतलब यह हुआ कि 3 महीने से ज्यादा की सज़ा इस चैप्टर के तहत, summary trial के तहत नहीं दी जा सकती है। तो जिसकी सज़ा 7 साल है, जिसकी सज़ा 3 साल है, जो cognizable offence है, उसको भी इसमें लाया गया है, मेरा इतना ही विरोध है, और कुछ नहीं। मेरा यह विरोध इसलिए है, क्योंकि आज जो जुडिशियरी की हालत है, बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे प्रावधान लाए, जैसा मैंने कल कहा कि आर्टिकल 39A में जो अमेंडमेंट हुआ, 42वें अमेंडमेंट के तहत कि गरीब लोगों को मुफ्त legal aid देकर उनको जस्टिस दिलाया जाए, यह सब कुछ हुआ, लेकिन lack of information के बारे में National Legal Literacy Mission लगाया गया, लेकिन यदि आप उसकी रिपोर्ट पढ़ें, तो पता चलेगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहां न्याय मिल सकता है?

उपसभापति जी, आज न्याय महंगा है और आज गरीब उस महंगे न्याय को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसीलिए हमारे पूर्व पुरुषों ने आर्टिकल 39A में संशोधन किया था। फिर भ्रष्टाचार है, जुडिशियरी में भ्रष्टाचार भी बहुत है और वह भ्रष्टाचार बहुत तरह का है, जैसे मैं कहता हूं कि adjournment का है। एक आदमी कचहरी पहुंचता है, उससे पेशकार कहता है कि आपका केस adjourn हो गया है, अगली डेट पड़ गई है, वकील अपनी फीस लेता है और वह बेचारा घर वापस आ जाता है, उसको 3 महीने बाद फिर कचहरी जाना है। भ्रष्टाचार भी बहुत तरह का है, फिर delays हैं, legal complexities हैं, geographical causes भी हैं। इन सारी चीजों को दूर करने की मंशा से ही यह विधेयक लाया गया है। जिस तरह मध्य प्रदेश ने पहल की, उसी तरह बंगाल सरकार ने भी एक पहल की थी और उन्होंने भी कोशिश की थी कि वे अपने यहां एक ऐसा विधेयक लाएं, जिसके माध्यम से वहां कोर्ट केसेज़ खत्म हो सकें, इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि pre-litigation issues को conciliation और mediation के माध्यम से, compromise के माध्यम से खत्म किया जा सके, लेकिन वहां एक जन-आंदोलन खड़ा हो गया, जिसके कारण उनको वह विधेयक वापस लेना पड़ा। यह वर्ष 2004 की बात है। हम एक तरफ केसों की संख्या कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, हो सकता है कि मंत्री महोदय कहें कि नहीं, नहीं सिर्फ यही बात नहीं है, हम तो गरीबों के दरवाजे पर न्याय पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम यह विधेयक लाए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, वह भी यही सारी चीजों की मंसा रखते हुए Fast Track Court लाई थी, लेकिन इससे pendency of cases कम नहीं हो सकी।

महोदय, मंत्री महोदय ने 17 अक्टूबर, 2008 को लोक सभा में जवाब देते वक्त कहा कि High Courts में जो civil और criminal cases पेंडिंग हैं, उनकी संख्या करीब 38,82,074 है। उसी तरह lower judiciary में करीब ढ़ाई करोड़ cases पेंडिंग हैं। जो हम ग्राम न्यायालय विधेयक लाकर यह चाहते हैं कि cases की संख्या कम हो सके, जब कि Lower judiciary में 73,35,749 civil cases और 1,84,74,595 criminal cases, दोनों मिला कर 2,58,10,544 cases पेंडिंग हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में करीब चलीस हजार cases पेंडिंग हैं, लेकिन ये सारे पेंडिंग cases को clear करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कचहरी खोलने की जरूरत है।

महोदय, अभी एक केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी। वह केस हुआ था, "The All India Judges Association and Others versus India and Others". उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए कहा कि लॉ कमीशन की 120वीं रिपोर्ट जो कहती है, उसके तहत इस पर कार्रवाई हो और जो आज per million populations अर्थात् दस लाख लोगों के पीछे सिर्फ साढ़े दस जज हैं। कहने का मतलब यह है कि आज दस लाख लोगों के पीछे सिर्फ 10.5 जज उपलब्ध हैं। उसको बढ़ाकर पचास जज करने की उन्होंने व्यवस्था करने के लिए कहा है, किंतु वर्तमान विद्वान मंत्री की कोशिशों से हम उसे 10.5 से 14 जज per million कर सके हैं, पर पचास को प्राप्त करने के लिए शायद हमें बहुत लंबा समय देखना पड़ेगा। जब हम इस विधेयक के

माध्यम से हर पचास हजार जनसंख्या पर एक ग्राम न्यायालय के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां देखते हैं कि करीब सात हजार blocks हैं और अगर हर एक ब्लॉक में दो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बैठाए जाएं, तो कम से कम चौदह हजार मजिस्ट्रेट्स की जरूरत है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, इसमें 20-22 हजार मजिस्ट्रेट्स का प्रावधान है। किन्तु क्या आज जो already Supreme Cout में, High Courts में और Lower Courts में pendency बहुत high हैं, उसको cover-up करके आप 22 हजार मजिस्ट्रेट्स और उपलब्ध करा सकेंगे? यदि आप उपलब्ध करा सकेंगे तो क्या आपने man power planning in judiciary a blue print was prepared in 1997 by Justice D.A. Desai, जिन्होंने 114वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट दी थी, उसमें एस.सी घोष member थे और इसी सदन, राज्य सभा, के भूतपूर्व Secretary General श्रीमती रमा देवी जी उसकी सचिव थी। उन्होंने यह रिपोर्ट जुलाई, 1987 में produce की थी। यह संख्या बढ़ाने के लिए, manpower planning करने के लिए जो जरूरत है, जो Judicial Administrative Training Institute हैं, वे कितने बनाए गए, उनके लिए क्या infrastructure उपलब्ध है, उसको देखने की जरूरत है। पर जिस तरह से यह क्रांतिकारी विधेयक लाया जा रहा है और जो बार-बार कहा जा रहा है कि गांव के लोगों को, गरीबों को, उनके द्वार पर न्याय दिलाया जाएगा, उसके लिए जो बेसिक ढांचा चाहिए, तो हम दस हज़ार करोड़ या बीस हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ राज्यों को भेज दें और उससे ढांचा तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचकर क्या आपने इस pendency को कम करने के लिए, क्या आपने गुजरात के मॉडल को कभी सोचा कि morning और evening court में हम इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं या नहीं?

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए और sum-up करते हुए जो सवाल बार-बार मैं उठा रहा था summary trial का और जो लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, कम से कम मैं चाहता हूं कि बिल को लाने से पहले, ड्राफ्ट करने से पहले विधि विभाग उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने अभी कहा कि सैक्शन 262, लेकिन आपके क्लॉज़ 14 में लिखा है—

> "Where the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, add to or omit any item in Part I and Part II of the First Schedule or Part II of the Second Schedule, as the case may be, and it shall be deemed to have been amended accordingly."

महोदय, यह क्लॉज़ इतना खतरनाक है, जैसा मैंने कहा कि जो प्रावधान summary trial summon case को डील करने के लिए है, उसमें आप warrant case को डील कर रहे हैं, जहां सजा तीन साल से सात साल है और उसमें प्रावधान भी रख रहे हैं कि आपने "delete" का तो लिखा, किंतु "add" का भी लिखा है। कल को आप add भी कर सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारे Indian Penal Code में 402 सैक्शन हैं, one stroke में आप सबको ले आएंगे summary trial के अंदर और यह प्रावधान आपके पास है, तो उसका उल्लेख आपने क्यों नहीं किया? मुझे वही आश्चर्य हो रहा है कि Cr.P.C. का सैक्शन 260 क्या कहता है? वह कहता है—

> "The power to try summarily notwithstanding anything contained in this Code, any Judicial Magistrate, any Metropolitan Magistrate, Magistrate of the First Class especially empowered in this behalf by the High Court may, if he thinks fit, try in summary way all or any of the following offences." और ये following offences कौन से हैं? ये following offences वही हैं, जो आपने Schedule 1 में लिखे हैं, पर Schedule 1 में इन offences को लिखते वक्त आपने कहा कि चोरी की संख्या 20,000 होनी चाहिए, तो आपने इसमें क्या लिखा है? Cr.P.C. कहता है कि वहां चोरी का amount "Does not exceed 2000 Rupees." आपने ज़ीरो लगा दिया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि ग्राम न्यायालय बिल को लाकर इतनी बहस न होती, अगर आप Cr.P.C. के सैक्शन 260 का संशोधन करते हुए वहीं कह देते कि यह 2000 की जगह 20,000 होगा और ये प्रावधान आ जाते, इस पर इतनी लंबी बहस न होती ! पर जिन लोगों ने इसको ड्राफ्ट किया, जिन लोगों ने इस बिल को तैयार

किया, उन्होंने इसको नज़अंदाज़ किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह एक वाकयी revolutionary विधेयक है, सिर्फ देखना है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग न हो सके और वाकयी जो भारतवासियों का सपना है, हमारे पूर्व पुरुषों का सपना है, जो आर्टिकल 39(a) का सपना है, जो commitment है country के प्रति, वह पूरी तरह प्रतिलक्षित हो, न्याय deliver करते वक्त, यह कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand here to support the Bill. However, a few observations with respect to the Bill, I suppose, will not be out of place for better appreciation of the contents and any future modifications wherever opportunities arise. To start with, I would like to submit that this Nyaya Adhikari concept as regards Gram Nyayalaya was not conceived any time. Whenever we thought of Gram Nyayalayas, the concept even in the mind of Gandhiji was not a magisterial hierarchy. Today, this First Class magistrate comes from the hierarchy of criminal courts. That man, I do not know how many will be attracted to this post because he has no future in the promotional hierarchy. Therefore, candidates would be less and less applying for this post. Moreover, the moment he gets any other opportunity, he will run away from the post. That is clear.

Secondly, if a person has to be qualified to be appointed as First Class judicial magistrate to be Nyaya Adhikari, why will he go for this Gram Nyayalaya? That is also a question. Therefore, this concept is a bit strange and it has to be given a fresh look. As I said, initially when I learnt about the Bill, at many places in my States I had been mentioning this to people, time and again, that such a Bill would be coming. I thought this was going to come under that concept which Gandhiji had conceived, namely, giving powers to Panchayat bodies to decide on disputes. जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। पंचायत बैठती थी और डिसाइड करती थी कि क्या करना चाहिए। I also thought, similar body will be elected for the purpose of giving justice; either of the two. That means, giving Village Panchayat or Panchayat body power to dispose of cases on merit.

Now, this is totally a different concept. Nevertheless, this has to be welcomed from the point of view that justice is further taken to the lower rungs which was available at a little higher level. It is now being taken further down. That concept should be appreciated. But, nevertheless, this does not fit into that concept of Nyayalaya.

I may recollect here late Rajivji's role in bringing the Constitutional amendments. It is he who conceived the Constitutional status to Panchayat bodies. Nobody had thought. There is hardly any mention of Panchayats in our Constitution till he conceived. He went to all the States, met Sarpanchs, Panchayats, Deputy Collectors, Tahsildars; at that time, I recollect objections were raised by Leftists saying that the Prime Minister of India has no business to meet Sarpanchs, has no business to meet Collectors or Deputy Collectors, and that it infringed the State's authority. This was the allegation made against Rajivji. But Rajivji nevertheless got the feedback from these people, brought them into the Constitution; of course, during his lifetime, the amendment could not come; subsequently, Narasimha Raoji brought it. But, it is he who did all the efforts to give the Constitutional status to Panchayat bodies which we never had.

Sir, Entry 5 of the State List mentions, 'Local Governments, that is to say, the Constitution empowers our municipal corporations, improvement trusts, district boards, mining settlements, authorities, and other local authorities for the purpose of local government or village administration.' This is the only mention you find in the Constitution before the 73rd Amendment. Therefore, this credit goes to Rajivji. I am told that initially Rajivji wanted to incorporate the justice through village bodies in that very Bill. But, ultimately, he was advised that separate treatment was required, *etc.* Therefore, things could not materialise at that time. If that had materialised, that would not have been a magisterial thing, I am sure about it. If that concept had materialised, it would have been a different thing and not a magisterial concept.

Even considering the magisterial concept, we conceived that authority to be created at village level, Gram. But, if you see the Bill, here, the stress is laid on intermediate-Panchayat, Taluka, not Gram. So, a cluster of villages in intermediate-level are considered. Gram is not considered as a unit for the purpose of constituting First Class Judicial magistrate. Therefore, in this sense also this does not address Gram, that is, *gaon*. If gaon had been there, then there would have been magistrate for every village or may be two villages. But here the stress is on intermediate level, this means this is a First Class Magistrate of tehsil level. So, it is tehsil not gram. Therefore, this concept that this is a Gram Nyayalaya is also not fitting. Secondly, now, Sir, I do not know when our hon. Law Minister had all the problems regarding consultations with High Courts with respect to various other matters, then here why has this concept of consultation been introduced here? In the matter of Gram Nyayalaya I do not understand it. As it is here, there are several problems right from the beginning with regard to the definition of consultation. We have been discussing about the definition of consultation for days together as to what consultation means. Here if you see, High Court has to be consulted in the matter of constituting Gram Nyayalayas. Now, limit has also to be decided in consultation with the High Court, constitution of Gram Nyayalaya is in consultation with the High Court, limit of Gram Nyayalaya is to be decided in consultation with the High Court, and then appointment of Nyayadhikari again is in consultation with the High Court. Therefore, I do not know how this consultation process will go on and what problems the Government will have to face from to time in each matter, I am not aware. Therefore, I think this consultation is a big hurdle in the matter of these Nyayalayas. Then comes the point of powers. I am avoiding the criminal jurisdiction. My colleague, Mr. Ahluwalia, has elaborated on that. I am coming to the Second Schedule, which deals with civil disputes. I am asking what is this right of purchase. It is not a simple thing, just mentioning right of *Panchs* and giving jurisdiction to Gram Nyayalayas, but right of purchase is under what law. Is it something under the Transfer of Property Act? Is it something under any local statute? Is it coming under Specific Performance Act? What is this we do not know? This is not a very small thing. Right of purchase is a thing whereby litigations are going on in various

courts for all these years, and certainly is not a thing can be solved by a Gram Nyayalaya. Therefore, this has to be elaborated and I think the hon. Law Minister will clarify this aspect. Then comes the use of common pastures. Now, as far as the use of common pastures is concerned, normally, there are local legislations dealing with it. So, what will be the jurisdiction of those authorities, which will deal with local pastures *etc.*? Then comes the timing. I mean small, small things have been put in a way as if application of mind is not there as far listing of subjects is concerned. Timing of taking water for irrigation — as far as water for irrigation is concerned, timing will not be the only aspect, and there may be so many other aspects also. But only the timing has been included. That will also create problem. So, other aspects relating to water will remain. Regarding farmhouse, — as my colleague mentioned, - I do not know what a farmhouse in Delhi means. A farmhouse in a remote village is a different thing, where farmhouse means a small house where you keep your utensils for the purpose of sowing, ploughing, *etc.* And in Delhi a farmhouse means a house of Rs.50 crores! Therefore, how farmhouse will be decided by Gram Nyayalayas I do not understand. One or two items I would like to mention which should have been added in the secondary rules and one of them is that we face mutation problem, land survey. People have to face a lot of problems regarding mutation. When somebody purchases land, he has to mutate it in his name and there is some procedure involved at *taluka* level. Now this power could have been given to this Gram Nyayalaya. Then comes the rights of agricultural tenancy, then we have the rights of the tenant, whether he is evicted or somebody has encroached upon a small agricultural plot, these things could have been given to it. In my place it is called the *Munkas.* A similar concept is there in Kerala. *Munkas* means in the property of another person somebody stays in a small house. He has been given the right. That is called *Munkas* and he gets the right of 300 metres in my State. Now there are disputes between the landlords and the *Munkas* in my place. Such disputes could have been entrusted to them. Small matters under Rent Control Act also could have been entrusted to them. Right of water or right-of-way, — about right of water I am talking in broad terms, *i.e.* irrigation — Right-of-way, *i.e.* easements are usual things on which villagers fight. On these things nobody can afford to go to a civil court, ask for a declaration under Specific Relief Act paying thousands of rupees to lawyers. Therefore, these are small things which, in fact, really require to be attended to and could have been included in this legislation. I am referring to summary procedure referred to by Shri Ahluwalia. Now, I have an objection to summary procedure on a different ground. Summary procedure is not a small thing. Even if a judicial magistrate is not well versed in law, it is easier for him to write verbatim proceedings. But, if he has to write it in a summary way — we know in school days how comprehension was so difficult if we had to reduce a paragraph of 15 lines into three lines — is difficult. So, this judicial magistrate would summarily summarise new and fresh statements of a witness and reduce it into summary way, which is a very, very difficult job. On the contrary, if he were asked to write in verbatim he can

easily write it. Therefore, justice will suffer in case of summary proceedings. Then, Evidence Act is not applicable but principles of natural justice are. Now, to read Evidence Act is easy, to understand sections are easy, but, if you want to know what are the principles of natural justice you have to read several judgements of thousands of pages to know what the principle of natural justice is and in each case the principle of natural justice has been explained in a different manner. So, you can't read this principle anywhere in one line whereas you can read the provisions of evidence. So, it is not the simplification of the concept, it is a complication of the concept of natural justice. Therefore, if anybody feels like including this and replacing the Evidence Act with principles of natural justice is simplification, it is not correct. Therefore, Sir, as far as summary proceedings are concerned, I do not think they are correct. Then, come provisions regarding appeals. As far as judgement or orders passed by Gram Nyayalayas is concerned appeal lies to district court in civil matters and appeal lies to Sessional Courts in criminal matters. Now as it is, our district courts and session courts are so loaded that after Gram Nyayalayas so many cases will come day in and day out in filing appeals in districts and session courts. From where they are going to discharge and how they are going to discharge it, I don't understand unless only district courts and sessions courts are appointed or constituted for the purpose of hearing appeals. I do not know how far it will be practical. Therefore, somewhere some civil courts are many — district courts are limited — but in a *taluka* or a district there are so many civil courts. Some civil courts could have been given the powers of Appellate Court so that more avenues are open and there could have been speedy disposal of appeals under Gram Nayayalayas. Then, comes assistance of police to Gram Nyayalayas. Of course, you have said assistance should be given. Now, again the same question arises. As it is you don't get police force for normal duties. Where are they going to sit in Gram Nyayalayas to assist the Nyayadhish? It is very difficult. How many police forces will be required for this job on a day-to-day basis? I would like to know whether more additional posts are going to be created in departments for the purpose of this and they have to be given training. Their routine training is not sufficient for the purpose of giving assistance to Nyayaadhikaris.

Then, if Police is to be used for execution of decrees, orders, *etc.*, and unless they are well-trained and they have effective powers to execute decrees or orders, who is going to listen to them. Otherwise, even after pronouncement of judgements, these disputes will not be solved, because of improper execution.

Now, I come to finance. I think, the hon. Law Minister has made certain arrangements. I am not aware of the details. He has got plans to give assistance. But, that assistance has to be 100 per cent in all respects. In certain respects you may say that the Governments will give 100 per cent assistance. In certain matters you may say it is 50:50. If we have taken the responsibility as a Central Government to create this body, then it is our duty. As far as the Central Legislation is

concerned, we should not put any burden on the States, because it is our legislation, we have conceived it and the State Government are there only to implement it. So, financial assistance has to be given fully by the Government of India. Otherwise, the State Government will say, 'we have got our own Budget. We have got our own priorities. We have got finances for other things. We do not have finance for Gram Nyayalayas.' If they start saying like this, there will be a problem. I am not saying this only with regard to this legislation. Whenever a Central legislation is conceived, whenever a Central scheme is conceived, it has to be borne by the Central Government. Sir, sometimes, we say the share would be 50:50 or, sometimes, we say it is 75:25. No such arrangement is advisable. If we enact a scheme or a Central legislation, it is our responsibility to provide all the necessary things.

Sir, I now come to Rules. As far as framing of Rules is concerned, I have always been saying, they must be ready when a Bill is introduced if it is to be effective. They may come into force later on. Otherwise, it takes a lot of time in framing of the rules. Secondly, why two authorities for framing of the rules? In certain matters of formation, service, qualification of counsels, inspection of Gram Nyayalayas, Rules have to be framed under Clause 39 by High Court. In respect of salaries of Gram Nyayalayas, sitting fee for counsels, Rules are to be framed by the Government. These two bodies for the purpose of framing two different set of Rules, I do not know how far effective they will be. I would like to know from the hon. Minister as to why it is not possible to vest these powers with one body.

Sir, lastly, welcoming this Bill again, I still say that a day must come when we have to have Gram Nyayalayas as conceived by Mahatma Gandhi, not Gram Nyayalayas of Magisterial hierarchy. You give powers to the elected bodies in Village Panchayats to resolve the disputes. If you want to have separate elected bodies, you can have it. But, this is too much of duplication. Sir, these powers have to be given to Gram Panchayats. Let them constitute some Committee for the purpose consisting of Members or otherwise of citizens and those village bodies must exercise the powers only then the justice will be faster and really effective. Thank you very much.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Thank you Deputy Chairman, Sir. First of all, I would say that I hail from village. So, I need some relaxation in time, if possible.

Sir, I rise to support the Bill. This is a historic Bill. I congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill before this House. I commend the hon. Minister for the same.

Sir, I have given notice to move some amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to move the amendment at the time of third reading of the Bill.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, on the one hand, it has been stated in clause 21(2) that the complainant may take the help of advocates at his own expense and, on the other, the right has

been given to the accused to take the help from the empanelled lawyers. This double standard cannot be accepted. My submission is that both, the accused and the complainant, if they belong to the lower income group, should be given the opportunity to take advantage of the empanelled lawyers.

Then, it has been stated that the State language will be used for correspondences and arguments. The most striking characteristic of our country is 'unity in diversity'. In every State there are 3-4 languages. And, in the North-Eastern States, even some small social groups are having their own language. So, instead of the 'State language', it should be the 'mother tongue' of the accused and the complainant so that they can freely ventilate their grievances.

Then, Sir, in part 1 of the Schedule-I, a sense has been given that the punishment may extend up to two years. My question is this. What are these offences? These offences include: some dispute between two groups or two persons, minor clashes, hot exchanges, and likewise. For such offences, I think, the maximum punishment should be one year. So, it should be reduced from two years to one year. For serious crimes, we have existing laws.

In clause 19, there is a provision for summary trial. I am afraid that this clause may be misused. So, I would like to register my caution to those who will be pursuing the summary trials so that this provision should not be misused. It is better to avoid summary trial. If at all it should be there, it should be a considered case where the summary trial may be used.

Now, I come to some basic points. I endorse the views expressed by the hon. Member, Shri Shantaram, about the expenditure. Here, it has been stated in the financial memorandum that the expenditure will be shared by the Centre and the State in the ratio of 50:50. I am strongly opposed to it because the Centre has a mission to provide right of judicial access right at the doorstep. If any State, for want of fund, is not able to fulfil it, the mission of the Centre will fail. The financial liability should be only on the Centre. Especially for the North-Eastern States, it would be extremely impossible for the States to bear the expenses on this count.

Then, I would like to raise one important basic point. Even after 61 years of independence, why have the grassroot people not been considered? The reason is, our society is a class-divided society. Previously, it was caste-divided. And, that has not withered away. It has turned into a class-divided society. The ruling classes, the moneyed classes, this way or that way, manage to influence the judicial system. That is why, the judicial rights could not reach the grass-root people. Our laws have done little to contain those who are at the root cause for the sufferings of millions and crores of people; of peasantry who are committing suicides. These exploiters have been going unpunished, ages after ages, decades after decades. So, while the hon. Minister has bold enough to extend these judicial rights to the people at the ground level, this fundamental truth should be taken note of.

Sir, I will request the hon. Minister to recall one incident which happened during our freedom struggle. There was a conflict between the upper classes and the depressed classes. And, the British rulers offered communal awards, and against this decision, Mahatma Gandhi had to go on fast unto death. And, the result was the Pune Act. So, this conflict between the exploited and the exploiters; between the upper classes and the lower classes has not come to an end. It has not come to an end, and opportunities have to be opened up for these grass-root people. There is the fifth caste also, I have not mentioned it. It is considered as an outcaste. The *Dalits* have so far remained out of the ambit of the judiciary. We have to see how this facility could be extended to them. That point has to be taken into account. What are the problems faced by these people? The problem is, there is lack of information. They don't understand that they have rights of judiciary. They are not aware, as yet, of their right to judiciary; where to go and whom to approach. They don't know that. In the Bill, I don't find any clause or any mechanism which shows that this message of justice could reach the doorsteps of those people. There is no mechanism. I will urge upon the hon. Minister to keep a provision for it. And, while framing the rules, some provision should be made covering this. Gram Panchayat is the best instrument for fulfilling the task of this message and to provide these rights to the grass-root people. So, in some way, the Gram Panchayats may be attached to this system. The Gram Panchayat is the best place for this.

The other problem is the monetary problem. Heavy expenditure is incurred for hiring lawyers and for travelling from their place of residence to the Nyayalaya's office. If they are called on different dates frequently, they have to travel frequently. They have to incur this burdensome expenditure, and this is the reason why these people are not able to take advantage of their judicial rights. Sir, I was going through a journal called 'Mint'; it is a Wall Street journal. They have conducted a survey on the status of Indian judiciary and they had surveyed over 14,000 accused and complainants.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, how much more time will you take? Your Party's time is over.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I shall take three or four minutes more.

So, the result of the survey is that in 59 per cent of cases, they gave bribes to the lawyers, in three per cent cases, to the judges and in 13 per cent cases, to the judiciary officials. This information is given in the journal, Mint, which is a result of their survey. If this be the position — अरुण जेटली जी अभी यहाँ पर नहीं हैं। हम उनसे पूछते what would be his charges; hon. Minister, Bhardwaj *ji*, is now the Minister. So, his charges are beyond the reach of the common people. For this reason, to this date, they are unable to enjoy the facilities provided to them.

Sir, I now come to my last point. As the hon. Minister and Members here are aware, dalits, the downtrodden and weaker sections of the people, live in villages in clusters. These tribal and downtrodden sections have evolved among themselves a traditional system of judiciary. They do not bother about courts. They are even afraid of the courts, and so, they have evolved a system

of their own. I have myself witnessed this. When somebody is insulted or attacked, they go to the village leader. The village leader asks them to convene a meeting. A meeting of the leaders, the rank and file, is held in an open courtyard, and there the argument goes on. The complainant says what he has to say; the accused give answers and the argument goes on. If there is a deviation from the truth, the rank and file present there tells the person that he has not spoken the truth and asks him to come out with the truth. In the courts, it takes months together for truth to come out, but in a meeting among villages in an open courtyard, truth comes out in one single meeting and judgement is delivered by the jury formed by the villagers. What I mean to say, Sir, is that there is freedom of speech; there is an understanding among the villagers and a system is evolved with ease. Can the Gram Nyayalayas come up to that level? Here there is the Nyayadhikari. People are afraid of the court and its environment. Whenever they go to the court, they see some lofty persons coming there and get puzzled with their postures and gestures, the court system, bars and so on. But in the villages they do not get puzzled. So, I do not know whether these Gram Nyayalayas can reach up to that level. Sir, there are lakhs and crores of educated youth in our country. Will the hon. Minister frame one condensed course, distribute handbooks of law, practical books and impart training in a course of one year or six months so that we can train educated youths of the villages? Hundreds of youths would rush for it. He is known to the villages. Since he is known to the villages, he has got free access. By this way, the situation will be easy for them and they can take the benefits of this judiciary system. I am hopeful that the hon. Minister will try to make an orientation programme in that way, and the true spirit of this Bill will reach its destination.

**प्रो. राम गोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभापति जी। मैं सबसे पहले तो माननीय विधि मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सस्ता व सुलभ न्याय आम आदमी तक और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। महोदय, आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि एक गरीब आदमी को भी वकील कर के शहर, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जिससे अब उसे राहत मिली है।

उपसभापति जी, हमारे यहां तो पंच परमेश्वर के न्याय की अवधारणा थी जिसे हमारे विधि मंत्री जी ने बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल बनाने का काम किया है। इसके लिए मंत्री जी आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय दिलाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे और भी प्रशंसनीय हैं। महोदय, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना पढ़ा-लिखा आदमी भी मुकदमा लड़ता है। उसका वकील कोर्ट में अंग्रेजी में बहस करता है, लेकिन क्लाइंट को यह नहीं मालूम होता कि उसका वकील उसके पक्ष में बोल रहा है या विपक्ष में बोल रहा है। महोदय, हमारे यहां एक बार चकबंदी के मुकदमों में एक ऐसा मामला आ गया जिसमें एक बिना पढ़े-लिखे आदमी के खिलाफ फैसला हो गया। लोगों ने उसे कहा कि तुम्हारा वकील अंग्रेजी ठीक नहीं बोल सकता था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ फैसला हो गया। फिर वह इटावा की कचहरी गया और वहां पहले नंबर पर बैठे वकील साहब से पूछा कि कोई ऐसा वकील बताइए जो अच्छी अंग्रेजी बोलता था। वह वकील मेरे मित्र थे, उन्होंने एक वकील का नाम ले दिया। उन्होंने एक ऐसे वकील का नाम ले दिया जिनका pronunciation किसी की समझ में नहीं आता था। वह उन वकील को लेकर गया और उन्होंने बहस की। वहां जो Assistant Consolidation Officer था, वह समझ नहीं पा रहा था कि वकील साहब क्या कह रहे हैं। उसकी समझ में एक शब्द restoration आया। वह फैसला एक्स-पार्टी हो गया था, तो वह restore करने का मामला था। उस ऑफिसर को restoration समझ में आया और उसने उसे restore कर दिया। फिर वह client

ए.सी.ओ. के पास गया और उनसे कहा अब बोलो, बहुत अंग्रेजी बोलते थे। मेरा वकील अंग्रेजी बोलने आया है। महोदय, यह हमारे गांव के पास एक जसवंत नगर constitutency का मामला है।

महोदय, यह स्थिति है कि छोटे शहर या कस्बों में लोग अंग्रेजी समझ ही नहीं पाते। इस विषय में हमारे सांसद श्री नन्द किशोर यादव जी भी बोलेंगे, लेकिन मैं माननीय कानून मंत्री जी को बधाई देने के लिए बोलना चाहता था कि वह आम लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए इस विधेयक को लाए। इसमें ऐसे प्रोविजन्स हो सकते हैं, जिनसे थोड़ी-बहुत अड़चन आए, क्योंकि प्रेक्टीकली जब कानून अमल में लाए जाते हैं, तो उनमें दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन बाद में कभी, that is open to correction, अमेंडमेंट हो सकता है। ओवर-ऑल यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। माननीय कानून मंत्री जी, आपके मन में जो गांव और गरीब के प्रति उदारता है, उसके लिए धन्यवाद।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ।

**श्री शिवानन्द तिवारी** (बिहार): उपसभापति महोदय, यह जो बिल सदन के सामने पेश हुआ है, इसका जो मकसद इसकी भूमिका में बताया गया है, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इस बिल का कोई विरोध करेगा, इसकी संभावना नहीं है। इसके मकसद में बताया गया है—.."access to justice to the citizens at their doorsteps and to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen..." अब इस मकसद से किसका विरोध हो सकता है? मैं यह मानता हूँ कि जिस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है, उसी तरह से इंसाफ पाना भी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन मुझे इस बात की गंभीर आशंका है, जैसा मेरा अनुभव है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि हमारे यहां जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में अधिकांश मामलों में इंसाफ नहीं मिल पाता है। कहीं-कहीं ऐसा इक्का-दुक्का मामला आ जाता है, जिसके बारे में अखबारों में सुर्खियों में खबर छपती है कि इंसाफ के मामले में एक क्रांतिकारी फैसला हुआ है, लेकिन इन-जनरल देखा जाए, तो हमारे यहां जुडिशियल सिस्टम में इंसाफ नहीं मिलता है। जो साधारण आदमी है, उसको तो इंसाफ मिलने का सवाल ही नहीं है। जो समाज के बड़े-बड़े लोग हैं, वे हमारे जुडिशियल सिस्टम को मैनुपुलेट करके इंसाफ के साथ किस तरह से बेइमानी और धोखाधड़ी करते हैं, इसको भी हम सब लोग जानते हैं।

उपसभापति महोदय, अभी हम देख रहे थे कि हैदराबाद में चारमीनार के पास आतंकवादियों के द्वारा बम-विस्फोट हुआ था और कई लोग उस मामले में पकड़े गए, लेकिन पुलिस उनका अपराध साबित नहीं कर पाई। न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन उनको जो जेल में रहना पड़ा, उससे उनको जो माली नुकसान हुआ, उनकी प्रतिष्ठा को जो हानि पहुंची, उन पर जो दाग पड़ा, उसके बारे में जो एक-दो अभियुक्त थे, जो एक्यूज्ड थे, जो निर्दोष होकर रिहा हुए, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। उनकी नौकरी चली गई, आज उनको कोई अपना घर, कोई अपना मकान देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि यह आतंकवादी है। ऐसा जुडिशियल सिस्टम में होता है। आपने बरी तो कर दिया, एक ढंग से आप यह कह सकते हैं कि उनको इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या वाकई उस मामले में अभियुक्त होने के बाद उनकी समाज में जो हालत हुई है, कैसे आप कह सकते हैं कि उनको इंसाफ मिला? उनके साथ जो बेइंसाफी हुई इस जुडिशियल सिस्टम में, इस न्यायिक व्यवस्था में, उसको आप कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहां जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें इतनी कमी है कि उसमें सामान्य आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता है।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए]**

महोदय, यह जो बिल है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि जो आशक्त लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, किन्हीं कारणों से आज जो हमारे जुडिशियल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका दरवाजा नहीं

खटखटा सकते हैं, उनके लिए यह न्याय व्यवस्था उनके दरवाजे पर जाएगी और उनको न्याय देगी, लेकिन आप इस पूरे बिल को पढ़िए तो ऐसा लगता है कि हमारा जो एगजिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम है वह उसी का एक्सटेंशन है, उसी का यह विस्तार है, सारी की सारी व्यवस्था उसी तरह की है। यह जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसके बारे में मैंने कहा, यह इंसाफ देने में असमर्थ है, तो इसको एक्सटेंड करके आप कैसे इससे अपेक्षा कर सकते हैं कि यह जुडिशियल सिस्टम इंसाफ देगा?

महोदय, जो राजीव गांधी जी का नाम लिया जाता है। कम से कम उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया, जिसको 74वां या 75वां संशोधन कहते हैं, यानी पंचायती राज को संवैधानिक स्टेट्स मिला। उसमें आपने सरपंच की, पंच की व्यवस्था की है और जो कानून बने हैं, उससे उनको न्यायिक अधिकार मिले हैं। उसके जो कानून बने हैं, उनमें भी उसको अधिकार है, न्यायिक अधिकार है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बता सकता हूँ कि कई जगह ऐसे-ऐसे सरपंच हैं- मुजफ्फरपुर में एक महिला है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इस बात का मुझे अफसोस है। अखबारों में एक खबर छपी थी कि जब से वह सरपंच बनी है, एक भी मामला पुलिस थाने में नहीं गया है। उस सरपंच के प्रयास से स्थानीय स्तर पर ही मामला निपट जाता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक-डेढ़ महीने पहले की बात है। पटना शहर के किनारे एक ग्राम-पंचायत है, वहाँ हमको जाने का मौका मिला था। उस पंचायत की जो सरपंच है, वह पिछड़ी जाति की एक महिला है। कार्यक्रम के बाद हम उसके घर चाय पीने गये। हमें पता लगा कि वह सरपंच है। हमने उससे पूछताछ शुरू की कि तुम क्या काम कर रही हो, कैसा काम कर रही हो और कैसा तजुर्बा है? उसने हमें बताया कि उसने लगभग एक सौ मामलों का फैसला किया है। उनमें कई मामले ऐसे हैं जो पति-पत्नी के झगड़े के हैं जिन्हें पंचायत करके उसने निपटा दिया। कई मामले किरायेदार के हैं, परिवार के अंदर बंटवारे के हैं, जिन्हें उसने सुलझाया। हमें आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ आपने जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की है, पंचायती राज को इस देश में आपने लागू किया है, उसके अंदर जो न्याय का प्रावधान है, उसको बगैर एक्सप्लोर किये हुए, उसको ताकतवर बनाने के बजाए आप और हम जो सार्वजनिक जीवन के आदमी हैं, उनको इस बात का तजुर्बा है कि निचले स्तर पर हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, कितनी लूट है!

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें बिपिन चन्द्र पाल जी की याद आ रही है। लाल-बाल-पाल स्वतंत्रता आंदोलन के काफी नामी लोग थे। मैं बिपिन चन्द्र पाल जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। 1936 या 1938 में वह ऑटोबायोग्राफी छपी थी। जब अंग्रेजों ने ज्यूडिशियल सिस्टम को इस देश में लागू करना शुरू किया तो बंगाल में इसके खिलाफ भारी आंदोलन हुआ था। लोगों को लग रहा था कि यह इतना पेचीदा सिस्टम है कि हमें इसमें न्याय नहीं मिल पायेगा। हाँ, हमारे पंचायत की जो पुरानी व्यवस्था थी, पंच-परमेश्वर वाली बात थी। प्रेमचंद की कहानी "पंच परमेश्वर" को कौन नहीं जानता है। हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के कारण निचले पायदान पर जो लोग थे, शायद उनको जस्टिस नहीं मिलता था। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो मामला है, चाहे वह सिविल का मामला हो या क्रिमिनल का मामला हो, इसको पंचायती राज व्यवस्था से चुनकर जो लोग आये हुए हैं, उनको हर स्थान की जानकारी रहती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यह जो बिल है, जो मौजूदा हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, उसको विस्तारित करने का इसमें प्रावधान है। हमें नहीं लगता है कि मौजूदा न्याय व्यवस्था सामान्य आदमी को न्याय दे पाएगी। इसमें भी मजिस्ट्रेट है, इसमें भी वकील है, इसमें भी सब को डेट लेने की सुविधा रहेगी, तो हम कैसे अपेक्षा करें? इसलिए हमें आश्चर्य है कि जिस राजीव गांधी के नाम की दुहाई सत्ताधारी दल के लोग और माननीय विधि मंत्री देते हैं, उन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया और उस पंचायती राज व्यवस्था में न्याय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मजबूत करने, ताकत देने, उसको सक्षम बनाने के बदले जो मौजूदा न्यायिक व्यवस्था है, आप उसी का विस्तार करने जा रहे हैं। इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल को वापस लें तथा जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था में जिस न्यायिक प्रणाली की कल्पना की गई है, उसको ताकतवर और मजबूत बनाने की कृपा करें। इसी अनुरोध के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, I rise to support the Gram Nyayalayas Bill, 2008. At the very outset, I thank the hon. Minister who has brought forth this Bill in this House. Sir, this is a milestone in the history of judicial system of India. It is a historical Bill, I should say. You know, a few years ago, we passed 93rd Amendment to the Constitution, and through that Amendment, Panchayati-raj has come into existence. This is a revolutionary step, a historical step indeed. After that, this particular Bill is another milestone. Now, through this legislation, we are taking justice to the doorsteps of the people living in villages. That is why it is very important. We are not simply strengthening the judicial system; we are strengthening democracy itself. People will now get justice at their doors. There are a number of cases, thousands and crores, pending in the courts. "Justice delayed is justice denied". This is what we hear very often. Let us hope that these Gram Nyayalayas will certainly give justice in short time. Let us hope that there would be no delays at all. At the same time, justice has become very expensive. Poor people cannot afford to go to the courts in *taluka* places or district places. Now, this mobile court is a very revolutionary idea. These courts will go to each and every village wherever there are cases and, that is why, in a way, we are fulfilling the dream of Mahatma Gandhi. It may not be the same concept which *Gandhiji* had. Gandhi*ji* wanted to have Gram Panchayats. But, Panchayats, of course, have Executive function. It is the cardinal principle of our own legislation that there is separation of powers. So, that is why, Gram Panchayats are not having judiciary power in the village. These courts will be different. They will be independent and they will deal with the cases independently. I do not have much to say about this because elaborate suggestions have been given. I have a few suggestions. Litigation in villages is increasing. It is on the increase. Villages are divided on caste lines, on communal lines, even on political party lines. Villages are divided against themselves. So, there are conflicts and conflicts and conflicts in the village life. These courts perhaps will be reconciling that. There is a provision in this particular legislation that reconciliation will be done. This is a very good step. If some reconciliation is made between the parties, satisfactory answer will come. No particular piece of legislation is perfect. This legislation also cannot be perfect. Once it is implemented, we will come to know what are the difficulties, what are the hurdles, in the way and later on there would be amendments. But, speedy justice has to be given to the people. We have fast track courts; we have special courts; we have *lok adalats*; we have tribunals and now we are going to have these Gram Nyayalayas. *(Time-bell).* That is why I welcome it. The only request is that we should make a specific mention in the particular section that now pronouncements would be in the regional languages because common people cannot understand if judgements are delivered in English. They may argue in their own languages in the courts. Even their lawyers can argue in any language. But, the verdict itself should be written in the regional languages. This is one suggestion that I would like to make. Thank you very much.

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह ग्राम न्यायालय विधेयक इस सदन में लाए हैं और हमसे आशा करते हैं कि हम इसको पारित करें। कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा करते हुए मंत्री महोदय को बधाई भी दी है और उन्हें सराहा भी है। मैं एक अलग दृष्टिकोण से आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्यों में ग्राम स्तर पर न्याय सस्ते और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, इसका वर्णन किया गया है। इस उद्देश्य से किसी की भी असहमति नहीं हो सकती है, किंतु मेरा निवेदन यह है कि जो विधेयक आप लाए हैं, उसमें अदालतें, गांवों में चली जाएंगी, इतना कह देने मात्र से या करने से क्या सस्ता और सुलभ न्याय, गांवों के व्यक्तियों को मिल सकेगा? यहां प्रश्न यह है कि क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम इस ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य पावन होते हुए भी, उस पावन उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक से नहीं हो सकती है। जो न्याय व्यवस्था आज तक चली आ रही है, वह घिसी-पिटी है, उस पर नया कलेवर चढ़ाकर क्या आप सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करा देंगे? चाहे आप कितना ही क्रांतिकारी कदम उठा लीजिए, किंतु मेरा कहना है कि इससे उस उद्देश्य की पूर्ति बिल्कुल नहीं हो सकेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की मूल अवधारणा यह है कि मुकदमों से संबंधित पक्षकार, न्याय केन्द्र पर जाने के बजाय संविद पक्षकारों के बीच में जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सस्ता और सुलभ न्याय मुहैया कराने का जो उद्देश्य है, उसकी बात आपने कही है, किंतु क्या इससे मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी, क्या इससे मुकदमों के speedy trial and disposal में कोई सुविधा होने वाली है? अदालतें वही होंगी, प्रक्रिया वही होगी, उन्हीं वकीलों के माध्यम से प्रस्तुत कार्यवाही चलती रहेगी, time passing के लिए adjournments लिए जाते रहेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह सस्ता और सुलभ न्याय मुहैया कराने की दृष्टि से जिन तीन-चार बातों की मैंने चर्चा की है, इसके बारे में उनकी क्या राय है? ऐसे मुकदमे भी होते हैं, जिनके motives होते हैं, यह तो केवल window dressing की जा रही है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह व्यर्थ की कवायद है, जिसे आप कर रहे हैं, कृपया आप इस पर गंभीरता से विचार करिए। यह सरकार का अंतिम वर्ष है, हम अंतिम सत्र में बैठे हैं। शायद यह भ्रांत धारणा पैदा करने के लिए कि हम ग्रामीण जनता के हितैषी हैं, इसलिए हम सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करा रहे हैं और इसकी चर्चा क्रांति कदम के नाते की गई है, बड़ी वाहवाही की गई है, लेकिन कहीं यह वोट बटोरने की exercise तो नहीं है, इस पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण न्याय की व्यवस्था क्या हो, कैसी हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वास्तव में न्याय देने के लिए उस व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे एक प्रसिद्ध न्यायविद का कथन याद आता है, जो उन्होंने 60 वर्ष पहले कहा था कि वे कोर्ट ऑफ जस्टिस होने का दंभ नहीं करते, वे केवल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हैं। क्या मंत्री महोदय यह समझाने की कृपा करेंगे कि सस्ते और सुलभ न्याय की दृष्टि से केवल मात्र judicature होकर जो मंतव्य उन्होंने 60 वर्ष पूर्व प्रकट किया, उस बात की प्रतिक्रिया की जाएगी। मेरा तो निवेदन है कि इस विधेयक को लाने के बजाए इस प्रकार का तंत्र खड़ा किया जाता, जिससे विवादों का निर्णय स्थानीय स्तर पर हो जाता, माननीय मंत्री महोदय ने खुद चर्चा की है। मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से तीन साल पूर्व जब तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मध्य प्रदेश के प्रवास पर गए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में ग्रामीण न्यायिक व्यवस्था का एक अभिनव प्रयोग देखा था। उस क्षेत्र में लगभग अस्सी गांव हैं, जिनमें पिछले पांच साल से कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई भी मुकदमा अदालत में पेश नहीं किया गया है और वह सारा क्षेत्र litigation free बन गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवदेन करना चाहता हूँ कि वे स्वयं या अपने अफसरों को वहां भेजें और इसका अध्ययन करवाएं। मेरा निवेदन है कि कलाम साहब ने जिसका उल्लेख किया है, यदि उसको अदालती शक्तियां देकर उनको मान्यता दी जाए तो सस्ता और सुलभ न्याय

दिलाने की संविधान का जो मंतव्य है, उसे पूरा कर सकेंगे। मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में 60 से 70 के दशक के बीच में ग्रामीण स्तर पर सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्याय पंचों की स्थापना की गई थी, माननीय मंत्री महोदय के इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ग्राम पंचायत एक executive body है, उनको न्याय नहीं दिया जा सकता है। 60 और 70 के दशक में न्याय पंचायतों की स्थापना की गई थी, वे छोटे-छाटे विवादों का निर्णय कराती थीं, किन्तु अपना निर्णय enforce करने के लिए उनके पास किसी प्रकार की शक्तियां नहीं थीं, इसीलिए वे सफल नहीं हो पाई। फिर भी उन न्याय पंचायतों से ग्रामीणों को बहुत मदद मिली थी। मेरा ऐसा मानना है और निवेदन है कि सशक्त न्याय पंचायत व्यवस्था ही सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करा सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा कीजिए, 20-25 लोगों का एक penal तैयार कीजिए, विवादों को सुनने के लिए न्यायिक बेंचों का गठन कीजिए और इन बेंचों का गठन करते समय जो interested parties हैं, उनको confidence में ले लीजिए। यदि इंग्लैंड जैसे देश में प्रिवी-काउन्सिल व्यवस्था काम कर सकती है, जिसमें कोई विधिवेत्ता नहीं होता। क्या वह judicial authority नहीं है, तो क्या वह भारत देश में नहीं किया जा सकता है। यह विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस व्यवस्था को पुनर्जिवित कीजिए, study कीजिए, एडिशन कीजिए और उनको न्यायिक शक्तियां दीजिए।

महोदय, अब मैं इस विधेयक के कुछ अहम मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ग्राम न्यायालय, जहां तक संभव हो, पक्षकारों के बीच सुलह करा कर विवादों का समाधान करने का प्रयास करेगा, यह आपने एक्ट में लिखा है। इस प्रयोजन के लिए आप सुलहकारों का उपयोग करेंगे। जब आप सुलहकारों की नियुक्ति की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो क्या यह समीचीन नहीं होगा कि न्यायालय में आने के पहले ही ये सुलहकार इन्हें सुनें और विवादों का समाधान करें। आप अदालत ले जाएंगे और सुलहकार बनाएंगे, यदि सुलहकारों को अदालती शक्तियां प्रदान कर दी जाएं कि उनके द्वारा निर्णीत आदेश और निर्देश को डिग्री समझा जाए, तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि इस प्रस्तावित व्यवस्था की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आप यह विधेयक लाए हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र)**: कृपया समाप्त करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**: महोदय, अगर मैं कोई बिन्दु अलग बोलूंगा, तो आप मुझे मना कर दीजिए। अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र)**: समय की सीमा है।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र)**: हां, ठीक है, परंतु समय की सीमा है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ग्राम न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा। इसका क्षेत्राधिकार इससे लेकर मध्यवर्त्ती स्तर पर पंचायतों का समूह होगा, इसका बड़ा आशय है कि पंचायत समितियां ताल्लुका स्तर पर होंगी। अगर हम पांच-पांच पंचायतों का समूह बनाएंगे, तो आपको आज से अधिक, छः गुना मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने पड़ेंगे, six times ! यह बात तो ठीक कही, मंत्री महोदय ने अपने प्रस्तावित भाषण में कि यह खर्चा केंद्र सरकार करेगी, maybe. But is it not a burden on the public exchequer? छः गुनी संख्या आप लगाएंगे। एक तालुक में नहीं जा सकता, उसको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, जैसा आपने भी स्वयं कहा। न्यायाधिकारी समय-समय पर ग्राम पंचायत से उत्पन्न मुकदमों की सुनवाई के लिए जाते रहेंगे। यह एक विषय है, जिसके बारे में हम समझते हैं कि यह हो गया, तो आसमान टूट जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। न्यायाधिकारी को assist करने के लिए पक्षकार लोगों को अपने वकील भी न्यायाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। लिटिगेंट किसी तरह से तो अदालत में पहुंच जाता है, तालुक में फीस दे देता है वकील को, वकील ले जाओ, साथ मुंशी जाए, उनके खाने-पीने का प्रबंध करो, उतना खर्चा वहन करो — दिखने में तो बड़ा आसान दिखता है कि हमारी अदालत पहुंच गई doorstep पर, वह काम भी हो जाएगा। सस्ता, सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए मंत्री महोदय ने कहा था कि न्यायालय में आने वाले पक्षकारों का खर्चा हम वहन करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं

कि इस विधेयक में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था की गई होती, तो बड़ा अच्छा होता, किंतु जो व्यवस्था विधेयक में की गई है, उसमें भी 21(2) में, प्रस्तावित प्रावधानों को मैं शब्दशः quote कर रहा हूं — "उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय के समक्ष दांडिक कार्यवाही में परिवादी ग्राम न्यायालय की इजाज़त से अपनी पसंद के किसी अधिवक्ता को अभियोजन के मामले को प्रस्तुत करने के लिए अपने खर्चे पर नियुक्त कर सकेगा।" बहुत स्पष्ट है। अधिवक्ता का खर्चा परिवादी को देना होगा। ऐसी स्थिति में सरकारी खर्चे की बात कहां कही जा रही है? कहां है, कौन से कानून में है? उसमें क्या है, वह भी बताना चाहता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र)**: जल्दी कीजिए।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अगर मैं एक भी विषय इससे हटकर बोल रहा हूं और अलग भी बोल रहा हूं, तो मुझे आप बताइए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र)**: आप जल्दी करें, और लोग भी हैं बोलने वाले !

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं केवल दो मिनट लूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र)**: ठीक है, दो मिनट।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**: मैं निवेदन करना चाहता हूं, खंड 21(3) में, सवाल है — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार न्यायालय में अधिवक्ता की सेवाएं सरकारी खर्च पर आपराधिक मामलों में उपलब्ध करने का प्रावधान पहले ही है। अतः इस विधेयक में कोई व्यवस्था की गई है, कोई नयापन नहीं है।

जहां तक सिविल मामलों का प्रश्न है, अध्याय 5 में एक भी शब्द नहीं कहा गया है जो यह परिलक्षित करता हो कि सिविल मामलों में अदालती व्यय, अधिवक्ता पर होने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार के मुकदमे में होने वाले खर्चों की मदद लेगी, ऐसा विधेयक में कोई नया प्रावधान नहीं है। Adjournments लगातार लिए जाते हैं, पक्षकार थक जाए, इसकी योजना पूर्वक व्यवस्था की जाती है। इस योजना से वह उनमें किसी प्रकार का अवरोध होकर खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यह retrograde step है, अपनी न्यायव्यवस्थाओं की व्यवस्था को, ग्रामीण व्यवस्था को पुनर्जीवित कीजिए।

माननीय मंत्री जी ने फास्ट ट्रैक अदालतों की चर्चा की थी। सुनवाई में सुधार आया है। लंबा अरसा नहीं लगता। इन फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर ग्राम न्यायालयों के समक्ष आपने ही कहा कि कार्यवाहियों को विस्तारपूर्वक अभिलेखित करना आवश्यक नहीं होगा। मेरा मानना है कि यदि इसी प्रकार के अधिकार देकर न्यायपालिका का गठन किया जाए, तो गांवों में सस्ता और समय पर सारवान न्याय उपलब्ध होगा। यदि न्यायाधिकारी summary record के आधार पर कार्यवाही कर सकता है, तो क्या कारण है कि न्याय पंचायत ऐसा नहीं कर सकती? और न्यायालय में गांवों के लोग रहते हैं। अदालत में तो साक्ष्य और मामलात को फैब्रिकेट किया जाता है, किंतु ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत बैठेगी, जब गांव के लोग भी बैठेंगे। फैब्रिकेट करना भी आसान नहीं होगा, इस बात को भी माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से परखें और इसीलिए adjudication जो आगे होता है, वह ऊपर नहीं होगा। अंत में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप कृपया इस विधयेक को वापस लें और वास्तव में ग्रामीण स्तर पर सस्ता, सुलभ, सर्वांग और सर्वमान्य न्याय दिलाने के लिए एक सक्षम व्यवस्था का निर्माण करने के लिए ऐसी दिशा में चिंतन करें जिससे ग्रामीण समाज की समस्याओं का समाधान स्थानीय ग्रामीण समाज के स्तर पर स्थानीय ग्रामीण समाज के द्वारा किया जा सके। धन्यवाद।

**सुश्री सुशीला तिरिया** (उड़ीसा): धन्यवाद महोदय, जब आप चेयर पर होते हैं तब हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। महोदय, ग्राम न्यायालय बिल — 2008 लाने के लिए मैं हमारे आदरणीय हैट्रिक लॉ मिनिस्टर को बधाई देती हूं। कल उन्होंने संक्षिप्त भाषण में कहा था कि उनको तीन बार भारतवर्ष के लॉ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है इसलिए अब लॉ मंत्री जी अगर हैट्रिक लॉ मिनिस्टर कहलाएंगे तो अच्छा होगा और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं कि देर से ही सही

लेकिन दुरुस्त तरीके से बहुत सालों के बाद यह ग्राम न्यायालय बिल आया है। बहुत सालों से, हर सेशन में ग्राम न्यायालय बिल लाने के लिए बिज़िनेस में लिस्ट अप होता है लेकिन आ नहीं पाता है। सर, 73 अमेंडमेंट पंचायत राज थ्री-टायर बिल लाने का राजीव गांधी जी का भी सपना था। मुझे याद है, इसी हाउस में दो वोट से वह बिल पास नहीं हो पाया था। आज मैं ग्राम न्यायालय पर भाषण सुन रही थी। सर, देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी का कहना था कि, "the last man in the last part of the village gets justice". आज उनके इस सपने को पूरा करने के लिए और महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि गांव में लोगों को न्याय मिले — बेसिकली मैं देख रही हूं कि इस बिल में वह प्रावधान है। महोदय, शहर में तो हर किसी के लिए कानून दरवाज़े के सामने है लेकिन गांव में गरीब, आदिवासी महिलाओं के लिए गांव में दरवाजे के सामने तो क्या, बहुत दूर-दूर तक जाने पर भी न्याय नहीं मिल पाता है। सर, मुझे एक सांसद के रूप में लोक सभा और राज्य सभा में काम करने का जो मौका मिला, मैं मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों और नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश ट्राइबल इलाकों में गयी और वहां पर मैंने देखा, मेरे पूर्व वक्ता और सीपीएम के भाइयों ने भी कहा, वहां पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी कानून क्या चीज़ है, यह भी उनको सही तरह से पता नहीं है। लेकिन आज ग्राम न्यायालय बिल — 2008 के जरिए गांवों तक न्याय पहुंचेगा। महोदय, इस बिल पर चाहे क्रिटिसिज़म हो — सत्ता में बैठे हुए और विपक्ष के माननीय सदस्य अगर कहते हैं कि उसके अंदर कमियां हैं — मैं मानती हूं कि कमियां हैं लेकिन कमियों को अमैंडमेंट के द्वारा बाद में सुधारा जा सकता है लेकिन जो स्टेप है, जो इनकी सोच है और जिस सोच के बाद वे यह बिल लेकर आए हैं, इसे लागू करने की जो इच्छा शक्ति मंत्री जी ने जाहिर की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी को, सरकार को और यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देती हूं। महोदय, इस बिल में यह देखना चाहती थी क्लॉज़ 32 (2) not bound by the provisions of the Civil Procedure Code, 1908 or the provisions of the Evidence Act, 1872 के तहत यह गाइड नहीं होगा, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत यह अपना own procedure और टाइम regulate करेगा, जहां जहां पर मोबाइल कोर्ट की जरूरत होगी। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि जनरली ट्राइबल इलाकों में बहुत स्कैटर्ड गांव होते हैं, दूर-दूर तक गांव फैले होते हैं। मैं आज हाउस को यह भी बताना चाहती हूं कि डीलिमिटेशन के बाद ट्राइबल इलाके की पापूलेशन किस तरह से स्कैटर्ड है। कानून तो दूर की बात है, वहां पर पापूलेशन भी धीरे-धीरे घटती जा रही है और डीलिमिटेशन के बाद काफी सारी कॉन्स्टीट्युऐंसीज़ में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल सीट्स खत्म हो गयी हैं। इसलिए हमें वहां के माहौल के बारे में पता होना चाहिए कि वहां किस तरह से स्कैटर्ड विलेजिज़, स्कैटर्ड गांव और घर हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट तहसील तक जाना उनके लिए संभव नहीं होता है, इसके लिए बहुत खर्चा होता है। इसलिए सुलभ और सस्ता कानून गांवों तक लाना एक बहुत अच्छा कदम है। सर, दूसरे मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें तहसील के नीचे और पंचायत के ऊपर ग्राम न्यायालय की जो कोर्ट है उसमें ये लगेंगे। मैं यह कहना चाहूंगी कि आज के दिनों में भी बहुत सारी जगह में कोर्ट में जजेज नहीं हैं। अभी इस ग्राम न्यायालय के तहत आप पांच हजार कोर्ट गांवों में बनाएंगे और उसके लिए केन्द्र नॉन-रिकरिंग एमाउंट का हंड्रेड परसेंट भार लेगी और जो रिकरिंग फंड से पैसा है वह राज्य के ऊपर रहेगा। सारी जिम्मेदारी के बारे में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कंसल्टेशन विद दि हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस के साथ जो न्यायाधिकारी होंगे, उसमें इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं पुरानी चीजों को याद दिलाना चाहूंगी, जहां तक गांवों की बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यह प्रोसीजर, यह बिल और ऐक्ट, जिस पर काफी मेंबर्स बोल लिए हैं तथा अभी और बोलेंगे, लेकिन बिल तो बन गया है और अब केवल पास होना है। यह अभी शुरूआत है लेकिन आगे अमेंडमेंट में जो सुधार होगा, वह तब देखा जाएगा। लेकिन सर, मैं इसमें एक चीज के बारे में बोलना चाहूंगी, जो इस बिल के अंदर है और वह इसमें कहीं न कहीं छिपकर है। वह चीज एमिकेबिल सैटिलमेंट की है, जिसमें स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दस हजार का पनिशमेंट होगा और आई.पी.सी. के तहत उसमें डिसीजन न्यायाधिकारी करेंगे, जो फर्स्ट क्लास रैंक के मजिस्ट्रेट होंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि स्टेंडिंग कमेटी पनिशमेंट चाहे तीन साल या दस हजार कोई भी रिकमंड करे और बिल के अंदर एक हजार का फाइन तथा एक साल का जेल या पैनाल्टी कुछ भी उसमें रहे, वह अलग बात है। लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के मौलिक मुद्दे पर मैं बोलना चाहूंगी। एक समय ऐसा था जब हम बच्चे थे, कोई भी ट्राइबल इलाके की कोर्ट में केस करने नहीं जाते थे। उधर हर चीज एमिकेबिल सैटलमेंट के तहत होता था और गांव का प्रधान जिसको चौकीदार कहते हैं, वह सब को बुलाता था। एक गांव में पंच बैठता था और पंच के अंदर जो फैसला हो जाता था उसी को सब लोग मानते थे। आज जब हम लोग

कोर्ट कचहरी की बात करने लगे और एक मासूम, इमोशनल, सिम्पल और ओनेस्ट जो किसी तरह की उनमें अच्छाई छिपी है, उस अच्छाई को हम न्यायालय के नाम पर किस तरह खत्म कर देंगे, इस पहलू पर भी हमको देखना बहुत जरूरी है, ताकि इनको पनिश करने और कोर्ट में न्याय दिलाने से ज्यादा मैं सोचती हूं कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि एमिकेबिल सैटलमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह नहीं कि हम इसमें ज्यादा केसेज रखेंगे तो उससे ज्यादा वाह-वाही लेंगे। हमको यह नहीं सोचना है कि ज्यादा केस क्यों आए। केस को घटाने या कम करने का काम ग्राम न्यायालय के तहत क्यों एक्सेस्पनल रोल के अंदर नहीं रखा जाएगा। ट्राइबल इलाके में बैकवर्ड लोगों के अंदर, एस.सी., एस.टी. की महिलाओं के अंदर केस ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैं भाषण के तहत नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन मैं प्रेक्टिकल चीज बोलना चाहती हूं कि जैसा आजकल हर महिला के ऊपर कुछ भी हो जाता है तो उसमें डॉमेस्टिक वॉयलेंस, डॉवरी ह्रासमेंट की बात आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि ट्राइबल इलाके में किसी महिला के ऊपर कोई भी इशारा किया, आवाज किया या कोई अंगुली उठाई तो उसमें जो पंच-पांच लोग कहते हैं तथा निर्णय लेते हैं और बुलाकर उसके साथ शादी कर देते थे। डॉवरी ह्रासमेंट का कोई केस नहीं हुआ करता था या डोमेस्टिक वॉयलेंस का भी कोई केस नहीं होता था। इस तरह से एक सामाजिक सोशल जस्टिस की तरह सामाजिक न्याय उनके प्रति हुआ करता था। मैं यह कहती हूं कि इतनी अच्छी ट्रेडिशनल भारतीय संस्कृति है, उसी को ही डवलप करना है, उनको ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत है या इस बिल के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज रखनी चाहिए, क्योंकि जहां हमारी पौराणिक ट्रेडिशनल चीज है, अच्छाइयां हैं, इससे वह ज्यादा से ज्यादा बाहर भी जा सकती है। सर, इसमें एक और चीज है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के तहत ज्यादा एस.सी., एस.टी. की महिलाओं को इसमें जगह दी जाएगी तथा न्यायाधिकारी के रूप में, नए जजेज के रूप में लिया जाएगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि रेल विभाग में तथा अन्य डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर एस.सी., एस.टी. का कॉफी बैकलॉग है। उसी सिम्पल नौकरी में अभी तक भी backlog पूरा नहीं हुआ है। कल को जब न्याय अधिकारी और जजों का backlog निकलेगा, तब आप उस backlog के बारे में क्या करेंगे? इसमें जो SC, ST महिलाओं को ज्यादा मौका देने के लिए प्रावधान है, उनको जस्टिस देने के लिए और amicable को ज्यादा महत्व देने के लिए आप कैसे पूरा करेंगे? सर, जो इसमें punishment की बात है, मैंने पहले भी बताया है, किसी ने कहा है कि इसमें 6 महीने या एक साल की punishment का ड्यूरेशन रहेगा और तीन दिन के अंदर दोनों पार्टियों को जज्मेंट सुनाया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष में इतनी सारी चीजें पॉलिटिकल हो गई हैं, गांव के लोग जिस पॉलिटिक्स को भली-भांति नहीं जानते थे, वे भी आजकल पॉलिटिक्स जानने लगे हैं। जैसे फिलिपीन्स में तथा मैक्सिको में मोबाइल कोर्ट्स हैं और उन्हें जस्टिस ऑन व्हील्स कहते हैं, वहां इस किस्म की मोबाइल कोर्ट का भी प्रावधान है। दूसरे कंट्रीज में भी मोबाइल कोर्ट्स हैं, वहां पर भी मोबाइल कोर्ट्स का प्रावधान है। जहां पर दिनदिहाडे सिक्योरिटी के साथ पुलिस की वैन से वोटर मशीन के बॉक्सेज चोरी हो जाते हैं, तो इससे हारने वाला व्यक्ति भी गुंडागर्दी करके जीत जाता है। आप मोबाइल कोर्ट के तहत उस गांव में without any फुलफ्लैज्ड सिक्योरिटी मोबाइल वैन या कोर्ट से, इन गरीब लोगों को जस्टिस दिलाएंगे, यह भी बहुत सोचने की बात है! इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जैसे इलैक्शन कमीशन ने गांवों में जाकर फोटो आइडेंटेटी कार्ड बनाने शुरू किए हैं और जैसे इलैक्शन कमीशन की जिम्मेदारी गांव में फोटो आईडेंटेटी कार्ड पहुंचाने की है, आप भी इसी तरह का कोई प्रावधान रखिए कि वहां पर फुलफ्लैज्ड मोबाइल वैन हो, जिसमें आप अच्छी तरह से मोबाइल कोर्ट को चालू कर सकते हैं। उसी तरह से उसमें काउंसलिंग का साधन हो, रिकार्ड मैंटेन करने का साधन हो और रिकार्ड खराब होने की संभावना भी न हो।

महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत से फंड की जरूरत है, जैसे जजों का एपॉइंट करना और बिल्डिंग न हो तो मोबाइल कोर्ट की भी व्यवस्था करना है। अब भारतवर्ष इस दिशा में जागा है, जहां पर अब गांव में पंचायत राज के तहत, कार्य शुरू हुआ है, वहां पर अभी पंचायत की अपनी बिल्डिंग्स नहीं हैं। कहीं-कहीं तो किसी के verandas में पंचायतें चल रही हैं और कहीं पर किसी के घर पर किराया देकर पंचायतें चल रही हैं। जो यह आपका मोबाइल कोर्ट है या ग्राम न्यायालय है, आप इसको क्या पंचायत आफिस में शुरू करेंगे या पंचायत आफिस के ऊपर करेंगे या किसी का घर किराये पर लेकर करेंगे या जैसे खुले में eyes camp लगते हैं, वहां पर करेंगे, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ग्राम न्यायालय

में awareness होनी चाहिए। गांव में पंचायत के तहत यह होना चाहिए कि यदि आप यह काम करोगे, तो आपको इसका दोषी माना जाएगा। इस तरह की पब्लिसिटी पंचायत में होनी चाहिए कि 107 सैक्शन क्या है, मर्डर केस क्या है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या है, सिविल केस क्या है, प्रॉपर्टी केस क्या है और IPC तथा CRPC के तहत आप यह सब करेंगे, तो आपके लिए इस दंड का विधान होना है। कम से कम इन सैक्शन्स को पढ़कर एक दूसरे के साथ बातचीत करके, जानकारी ले लें कि हम इस गुनाह को न करें, क्योंकि इसके करने से हमें इसका दोषी पाए जाने की संभावना हो सकती है। ग्राम न्यायालय को इस तरह की awareness की भी बहुत जरूरत है। फर्स्ट राउंड में जो पंचायत राज का चुनाव हुआ था, तो उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया और गांवों में यह चर्चा होने लगी कि महिलाओं के पति पंचायत चला रहे हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड में चुनाव हुआ, तो उस समय यह बोला गया कि महिलाएं अभी सक्षम हो गई हैं। अभी गांव-गांव में यह भी होना चाहिए ग्राम न्यायालय में awareness हो। पहले से ही रेडियो और टेलीविजन में यह आना चाहिए कि ग्राम न्यायालय बिल पास होने के बाद — अभी मेरे भाई श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक ने भी कहा है कि अभी जो forest land बिल पास हुआ है, उसको 6 महीने से भी ज्यादा समय होने को हैं, लेकिन अभी तक उसका रूल ही नहीं बन पाया है। मैं यह कहना चाहूंगी कि आपकी नीयत बहुत साफ है, आपमें इच्छाशक्ति है, इसलिए आप रूल्स को जल्दी से जल्दी फ्रेम करके इसे लागू करने की कृपा करें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए रिपीटिडली उन्हीं चीजों को न बोलते हुए सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। एक चीज आखिर में बोलना चाहूंगी कि आप देश में, ग्राम में पंचायत राज सिस्टम के तहत ग्राम न्यायालय बनाइए, गांव के लोगों की भलाई कीजिए, लेकिन देश में एक चीज हो रही है कि रीयूनिफिकेशन ऑफ एमीकेबल सेटलमेंट गांव में बाधा सृष्टि कर सकता है। गांव में देशात्मक जातीयता घटती जा रही है। पहले टेजीविजन पर कानून के साथ-साथ देशात्मक गाने दिखाए जाते थे, लेकिन आज के दिन, जब आप कोर्ट शुरू करने जाएंगे, तो मेरा यह निवेदन है कि देशात्मकता या जातीयता बोध का कोई गाना सुनाकर कार्य शुरू करना चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगी कि जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो सबसे पहले *रघुपति राघव राजा राम* की प्रेयर हुआ करती थी, उसके बाद एक क्लास हुआ करती थी कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले बम ब्लास्ट में, जब पूरा देश *ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी* वाला लता मंगेशकर का गाना देख रहा था, तो ऐसा लगता था कि यदि देश कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो पूरा भारतवर्ष उसमें कूद जाएगा। आप जब तक यह अहसास, यह देशात्मकता की फीलिंग, जातीयतावाद की नेशनल फीलिंग लोगों के बीच में नहीं डालेंगे, आपस में केवल क्रिमिनल बनाते जाएंगे, उनके लिए कानून बनाते जाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मैं यह कहना चाह रही हूं कि बच्चों को एक बार जुवेनाइल में रखने के बाद, आप जितने भी कोर्ट, पनिशमेंट, जुवेनाइल बनाइए, जब इंसान सुधरता नहीं है, वह दुबारा कुछ क्राइम करना चाहता है, तो उसमें मन में इस तरह की भावना पैदा करनी चाहिए कि They are bound to be an amicable settlement. जो ग्राम न्यायालय ज्यादा एमीकेबल सेटलमेंट करता है — आपने बताया है कि उधर ही रिटायरमेंट होनी है, उनकी न तो प्रोमोशन है, न ही उतनी तनख्वाह है, रिटायरमेंट भी उधर ही होनी है, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि गांव में जहां-जहां केंद्र सरकार के ऑफिस हैं, वे वहां जाते नहीं हैं, बहुत सारी सीट्स अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, आपके न्यायाधिकारी, जो ट्रांसफेरेबल है, जब ट्रांसफर होगा तो गांव में जाने का कष्ट भी करेंगे, यदि आप उधर ही रिटायर कर रहे हैं तो उनके बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे, यह चीज हंड्रस परसेंट गलत नहीं है, हमारी इच्छा अच्छी है, इसमें हंड्रड परसेंट कमी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज के दिन में अच्छे-अच्छे लोग, ऑफिसर, जज, सभी अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ और अच्छी शिक्षा देने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि उनके लिए भी कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिए। जिसने ज्यादा सेटलमेंट किए हैं, उसके लिए रिवार्ड, अवार्ड और तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वह गांव में न्यायाधिकारी बनकर पोस्टिंग क्यों लेगा? क्यों नहीं वह शहर में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में रहेगा, क्योंकि उनके लिए वहां स्पेशल कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, सबसे पहले हमारी यूपीए चेयरमैन और लॉ मंत्री जी को इस इनिशिएशन के लिए बहुत बधाई और देना चाहूंगी। धन्यवाद।

**श्री नन्द किशोर यादव** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आदरणीय कानून मंत्री जी ने जो "ग्राम न्यायालय 2008" विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय

मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस देश की ग्रामीण जनता की जो एक तरह से मांग थी, उन्होंने उसे पूरा करने का काम किया है। उन्होंने देश की ग्रामीण जनता और देश के निवासियों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए इस विधेयक को पेश किया है। उनकी जो मंशा है, उसी मंशा के हिसाब से इस विधेयक के अंदर तमाम प्रावधान भी हैं। मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं। सर, आज निर्धन और जिनके पास सुविधा नहीं है, उनके लिए न्याय और न्यायिक प्रक्रिया एक कठिन समस्या है। संविधान का अनुच्छेद 39(ए) राज्य को यह निदेश देता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने की बात कही गई है। सरकार ने इस आदेश को प्रभावी करने के लिए, जो संविधान के अन्दर कही गई बात थी, उसको कारगर ढंग से लागू करने के लिए इसके पहले भी तमाम तरह की व्यवस्था करने का काम किया। जैसा अहलुवालिया जी बोल रहे थे, एनडीए सरकार में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। त्वरित और जल्दी मुकदमों का निपटारा हो सके, आज निचली अदालतों में देश के अन्दर चार करोड़ से भी ऊपर मुकदमे विचाराधीन हैं, जल्दी से उनका फैसला हो सके, इसके लिए लोक अदालतों का गठन हुआ, जहाँ सुलह और समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण होता था। इसके लिए विशेष न्यायालय भी बने, अधिकरणों की स्थापना की गई। इस विधेयक के आने से पहले इस तरह की व्यवस्था सरकारों के द्वारा की गई। लेकिन हम लोगों के गाँवों में एक पुरानी व्यवस्था भी थी। पहले गाँवों में सरपंच हुआ करते थे। जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत छोटे-छोटे किस्म के मुकदमे, जिनमें 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक की सीमा के जो वाद रहते थे, उन्हें सरपंच लोग गाँवों में सुलझा लिया करते थे। उस समय पंचायतों में और उस क्षेत्र में सरपंच लोगों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। उनका चयन भी बहुत सही ढंग से होता था। हर ग्राम सभा से अदालत पंचायत के लिए दो आदमी का चुनाव होता था और दो-दो आदमी करके इसका गठन होता था। फिर जो सदस्य होते थे, वे सरपंच का चुनाव करते थे और जो छोटे-मोटे विवाद होते थे, उनको हल करने का काम सरपंच के द्वारा होता था। आदरणीय मंत्री जी ने यह जो विधेयक पेश किया है, वह एक बहुत अच्छा विधेयक है। आज निचली अदालतों में तमाम मुकदमों का अम्बार लगा हुआ है। आज जितने मुकदमे लम्बित हैं, देश के अन्दर न उतने न्यायालय हैं और न न्यायाधीश हैं। गरीब आदमी का छोटे-से-छोटा मुकदमा है, मान लीजिए पारिवारिक मुकदमा है, छोटे-मोटे बँटवारे का विवाद है, आजकल घरेलू हिंसा विधेयक पारित हो गया है, जिसमें रोज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बच्चों के गुजारे भत्ते का सवाल है, जो तमाम मामले हैं, वे आज न्यायालयों में भारी संख्या में विचाराधीन हैं, निश्चित रूप से यह जो विधेयक आया है, जब कानून का शक्ल लेगा, तो गाँवों में इनका निपटारा हो जाएगा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, भारत के विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की। मुझे याद है कि 15 मई, 2007 को राज्य सभा के अन्दर इस विधेयक को रखा गया था। बाद में इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी की करीब 22 रिकमेंडेशंस आईं। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आईं, उनको उन्होंने इसमें शामिल करने का काम किया और इस विधेयक को पेश किया। सर, गांव का आदमी, जो खेती का काम करता है अथवा दैनिक मजदूरी करने का काम करता है, अगर उसके ऊपर कोई मुक़दमा हो जाए या वह कोई मुक़दमा दायर कर दे, तो आज जैसी न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें बहुत पेचीदगी भरी हुई है। एक तो वह 40-50 किलो मीटर दूर से न्यायालय पहुंचेगा, फिर आजकल जो निचली अदालतें हैं, उनमें रोज छुट्टी हो रही होती है। यहां मैं निचली अदालतों के बारे में बता रहा हूं। किसी दुर्भावना से मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी आज़मगढ़ जिले में निचली अदालत में काम किया करता था, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि जो वकील लोग हैं, वे भी राजनीति का हिस्सा हो गए हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे ऊँचे न्यायालयों में तो यह ठीक है, लेकिन जो नीचे की अदालतें हैं, वहां भी किसी न किसी इश्यू पर राजनीति होती रहती है। मान लीजिए कोई वकील साहब स्कूटर से जा रहे हैं और बाई चांस किसी टेक्सी वाले से धक्का लग गया तो ...**(व्यवधान)**... यह मैं ऊँची अदालतों

के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन निचली अदालतों में इस तरह की बात महीने अथवा 20-22 दिन में इस तरह का अवसर आ जाता है। गरीब आदमी जो न्यायालय में जाता है, अगर उसका मुक़दमें का काम नहीं होता, सुनवाई नहीं होती, इस तरह उसे परेशानी तो होती ही है, साथ ही उसका आर्थिक नुक़सान भी होता है, उसके श्रम का नुकसान भी होता है।

यह जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें दीवानी और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो छोटे-मोटे पारिवारिक विवाद हैं, उनको सुलझाने का काम भी यह करेगा।

सर, इस विधेयक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो खंड 29 में दी गई है कि ग्राम न्यायालय की कार्यवाही और उसका निर्णय अंग्रेजी भाषा से भिन्न उसी राज्य की भाषाओं में से किसी एक में होगा। आदरणीय न्याय मंत्री जी ने यह सबसे अच्छा उपबंध लाने का काम किया है। इसके ऊपर हमारे नेता आदरणीय प्रोफेसर साहब ने भी विस्तृत रूप से बताया है कि आज हिन्दुस्तान के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, गांवों में आज भी वहां की जो लोकल भाषा है, चाहे वह भोजपुरी है, अवधी है, बंगाली है, कन्नड़ है या तेलुगू है, उसी स्थानीय भाषा में लोग बात करते और समझते हैं। इस विधेयक के माध्यम से अब उन भाषाओं में भी न्यायालय में काम-काज हो सकता है।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे मन में कुछ शंकाएं है, जिसे माननीय मंत्री जी दूर करने का काम करेंगे। आज भी समाज के अंदर तमाम तरह के शक्तिशाली लोग हैं, जो पैसे के आधार पर या बाहुबल के आधार पर शक्तिशाली हैं। जब यह कोर्ट या मोबाइल कोर्ट गांव में जाएगी तो कहीं न कहीं से यह जो प्रभावशाली क़िस्म के लोग हैं, वे दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस देश के अंदर तरह का वातावरण है, जिस तरह नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या बढ़ रही है, कहीं न कहीं यह शंका मन में पैदा होती है। जब साक्षी या गांव का आदमी न्यायालय में जाता है, जिलों में जाता है, तो वहां पर कोर्ट का जो कटघरा रहता है, उससे वह भयभीत रहता है और उसे उम्मीद रहती है कि यहां पर हमको न्याय मिल सकता है, लेकिन गांव में जब छोटी-छोटी पंचायतों के द्वारा विवाद को हल करने का प्रयास किया जाता है, तो उन पंचायतों में जो बाहूबली क़िस्म के लोग रहते हैं, वे अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मुझे कहीं न कहीं यह शंका जरूर है कि यह जो मोबाइल कोर्ट है, इसको कहीं धन बल या बाहुबल के आधार पर लोग प्रभावित करने का काम न करें।

दूसरा, जब तक इस न्यायालय के बारे में जनता के अंदर यह भावना पैदा नहीं की जाएगी कि जनता यह समझ सके कि इस न्यायाल से हमको न्याय मिलेगा, तब तक जिस मकसद और मंशा से आदरणीय मंत्री जी यह विधेयक लाए हैं, उसमें हमको कामयाबी मिल नहीं पाएगी। सर, तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन न्यायालयों के प्रति पुलिस का सहयोग किस तरह का रहेगा। आज थानों पर 20-22 से ज्यादा फोर्स के लोग नहीं हैं, तो किस तरह का उनका सहयोग रहेगा, किस तरह की उनकी कार्यप्रणाली रहेगी? यद्यपि इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि कोई आदमी खुद मुकदमा दायर कर सकता है या पुलिस द्वारा भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसमें पुलिस का सहयोग कितना रहेगा, उस पर भी यह निर्धारित करेगा इस न्यायालय के स्वरूप से ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष(श्री कलराज मिश्र)**: अब समाप्त करें नन्द किशोर जी।

**श्री नन्द किशोर यादव**: मैं खत्म कर रहा हूँ, महोदय।

एक आखिरी चीज़ मैं आदरणीय मंत्री जी से ग्राम न्यायालयों के बारे में पूछना चाहता हूँ। ग्राम न्यायालय जहाँ तक संभव हो पक्षकारों के बीच सुलह कराकर विवादों का समाधान कराने का प्रयास करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले सुलहकारों का उपयोग करेगा। इस तरह इसमें जो सुलहकार या समझौता कराने वाले नियुक्त किए जाएँगे, इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये जो सुलहकार हैं वे सरकारी सेवक होंगे या उस क्षेत्र के न्याय-पंचायत के सम्मानित लोग होंगे या पोलिटिकल वर्कर होंगे, इसमें किस तरह के लोग होंगे, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मैं आदरणीय विधि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक विधेयक लाया।

**4.00 P.M.**

सर, अभी बृजभूषण तिवारी जी बता रहे थे कि गांधी जी जब किसी मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ भी उन्होंने दोनों पक्षकारों को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास किया ...**(व्यवधान)**... समझौता करा दिया। इस तरह आदरणीय मंत्री जी का यह जो विधेयक है, उसमें समझौता कराने की प्रमुखता है। इसी के साथ मैं पुनः आदरणीय विधि मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पेश किया। धन्यवाद।

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Thank you, hon. Vice- Chairman. First of all I want to congratulate the hon. Law Minister for bringing in such a path-breaking Bill. In Marathi there is a proverb, *"Dev Deenaghari dhavala"* which means God runs towards the poor. I think, this Bill really means that as far as the poor and God is concerned. Hon. Member, Shri Ahluwalia in his speech had said that we call Nyayamurti, which means deity of justice. Here the hon. Minister has really taken the trouble to take God of justice to the remote village, to the doorstep of the aggrieved person. I wish to thank him. After 60 years of departure of Mahatma Gandhiji, this Government has finally lived up to what he said. He preached the principle of Gram Swaraj. Gram Nyayalaya, I think, is one step towards the concept of Gram Swaraj. It must be the rarest of rare occasions in the House where all Members are congratulating the Government. Here, while welcoming the Bill I want to bring a few suggestions and I want to express a few reservations about it. Please pardon me if I may repeat because I was not present in the House for some time. Sir, I am told, you have said that 3000 judges, first-class judicial magistrates would be earmarked for this job. Considering the vast scope of India, which is around 3 lakh villages, I do not understand how 3000 first class judicial magistrates would be able to encompass the whole country. If this is just a beginning, yes, it is a good suggestion. But, then, do not spread the scheme all over in one go. Let us go step-by-step, so that when you have around 40,000 to 50,000 Judges only then we will be able to implement this scheme all over the country. Otherwise, if there are only 3,000 Judges, my fear is, a Judge will not be able to visit the village of block for months together. If that happens, people will lose faith in the system. A good system will be defeated if you do not have enough judges.

Sir, secondly, the hon. Minister has said that Rs. 6.4 lakhs has been earmarked for a mobile court. It means, each month, a court will get around Rs. 50,000. Considering there will be a Judge, there will be bailiff, there will be 2-3 clerks, peons, driver, cleaner, petrol or diesel, AC car charges, salary of the judge, I do not think that Rs. 50,000 will be enough to meet this need. So, why do we make a poor court for the poor person? If the Government has good intention of implementing this scheme have some more funds so that these courts can work more effectively.

Another suggestion which many of my colleagues have made is...

SHRI H.R. BHARDWAJ: Will you yield for a minute?

There are lot of fallacies about these courts. Let me tell you, everything has been studied not only by the State Government and the Central Government but also by the Law Secretaries and the Registers- General of High Courts. For example, you have said about the recurring expenditure of Rs. 6.4 lakhs per annum. It is the expenditure which is being incurred on a

Magisterial Court today in all the provinces. So, we have adopted the scales of the High Courts and expenditures. So far as the capital expenditure is concerned for setting up of a court, 100 per cent will be reimbursed by the Central Government. So, these are two kinds of expenditure. The first one is for court room or for the vehicle like bus or jeep or any type of vehicle. For this, 100 per cent will be given by the Central Government. Then, recurring expenditure means the salary component for staff. So, this is what a Magistrate is using now. It has been calculated by the High Courts and this figure has been decided by a Joint Conference of the Law Secretaries and the Registrars-General. So, everything has been studied. You can give any amount of money. But, the States and the Centre and the High Courts have been consulted. And, the arrangement is that for every court 100 per cent expenditure on capital account would be reimbursed by the Centre. The State Government will pay for construction of Gram Nyayalayas and the Central Government will reimburse that amount. There is absolutely no difficulty in setting up of the courts.

Sir, coming to the number...

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: आप reply देंगे न?

**श्री हंसराज भारद्वाज**: इससे क्या होता है कि इधर-उधर की बातें होती हैं। Come to the point. Now, the people will know what it is. So far as the number of courts is concerned, again, my sister spoke about the tribal areas. We have excluded the tribal areas from the operation of this law. They have their own justice system and we do not intend to interfere in the tribal justice system. Let them continue with their own system. Then, it is voluntary for each State. It is not being thrust upon. For example, the State of Madhya Pradesh, after Soni's Report, started it. If they do not want the Grameen Court, let them not have it. I will enforce this Act State-by-State, not by notification. So, we should make our observation that it is a beginning. Then, it is not in a village. It is at the intermediate level *i.e.*, block level. How many blocks are there in the country? This exercise has also been done in the Simla Conference. So, we have done 6-7 years of work. We want to have suggestions which can improve the system.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): Mr. Raut, you have to conclude in five minutes.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: I stand correct, Sir. Thanks for giving me this information.

Sir, there are some observations and some more reservations that I would like to put before the House. One, if the trial is happening at the block level, near the village, I fear that when there are cases of theft or land grabbing or other such cases, if the evidence recording is happening within the situation there is a fear that the witnesses can be pressurised because the local people are around. In this situation, you will have to instruct the police department to keep a perfect vigil so that no witness is pressurised or terrorised. Even when the cases are in the district courts, I have seen the *goondas* of the interested parties standing outside the court and keep pressurising the witnesses and evidence-recording. And, when it happens right in the backyard,

there is a fear of this happening. Second, at the village level, there are cases between one person and another person, one family and another family, at the same time, there are cases against the *Zila Parishad*, against the *Panchayat* and against the Government. In that type of situation, what type of role this court will play? This point is also very important. It should not so happen that when the Government is in picture, when the Government is respondent, it should not happen that the Judge himself is pressurised because, after all, he is only a first-class magistrate; he is not a High Court judge or a Supreme Court judge. So, there is a possibility that there will be pressure on the judges.

My next suggestion pertains to the language used in the courts. Many have said that it should happen in the local language, and even the Bill suggests that. Within the State the languages differ. For example I come from Maharashtra, the languages and culture differ from Konkan to Vidarbha. So, if a case is happening in Konkan, I would suggest that you ensure the magistrate is from Konkan of course, that would be the responsibility of the State Government — that the judge comes from that region because the dialect differs, the culture differs, the problems differ, and even the family structures also differ. So, in that case, I think, we need to take proper precaution that both, the judges and the lawyers, come from the same region so that the proper justice can be administered.

There is one more suggestion for the hon. Minister. Now, the world is progressing, and while the world is progressing, I suggest that more and more avenues are coming forth. For example, now, internet is the buzz word. I understand there is no electricity in many villages, but there are literate people and literate youngsters. They would like to use internet on many occasions. Can this judicial system also take help of internet? Of course, the suggestion of 'e-justice' is a very broad suggestion, but since hon. Minister is taking progressive steps, I wish he also takes this into account.

With these words, I welcome the Bill. And, I only hope that whatever he has intended should come true. I also congratulate the Government that, at least, on the eve of the elections, six months before the elections, the Government has awakened and has brought forward this Bill. Thank you very much.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, this is a very important Bill that we are discussing. I would like to make a few observations for the consideration of the Minister and the Government. The Indian society had the concept of *panch parmeshwar*, where five chiefs of a village were treated equal to God. The village *panchayat* system has failed over the period of time due to bias, casteism and communal nature. In this background, the idea of bringing judicial courts to the village level is laudable. But, personally, I have a different understanding of the use of the word, *'Nyayadhikari.'* This can be used in normal judicial terminology, like 'judicial magistrate.' The whole effort of this Bill is to extend judicial services to the block level or *mandal* level. At the block level, we have block development officers. We know that. At the judicial level also, we can call them block judicial magistrates. But, that is not a major issue, but, I am pointing it out.

As far as reservation or appointment of these *Nyayadhikaris* is concerned, the Bill speaks about it on page 3. The Bill says, "The State Government shall, in consultation with the High Court, appoint a *Nyayadhikari* for every Gram *Nyayalaya.*" Then, it goes on to say, "While appointing *Nyayadhikari,* representation shall be given to the members of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women and such other classes or communities as may be specified by notification by the State Government from time to time." The provision for reservation for SCs/STs in the Bill is vague. I understand that. It says that as far as practicable, the Government should implement reservation. It does not mention about reservation for BCs and other categories. The State-level reservation, as applicable in a particular State, should be followed and reservation should be explicit.

Then, Sir, recruitment should be through competitive examination conducted by State Governments and not by High Courts, as seen in some States. These judicial officers should have normal promotional avenues, like normal judicial officers, otherwise, the level of frustration would rise. We are not creating old-time village *munsifs* or revenue clerks. I must underline this point. We are not trying to create old-time village *munsifs* or revenue clerks. The concept of bringing judicial services at the doorsteps of poor villagers is likely to increase litigation and not reduce it. This is my apprehension. I hope this system will also not suffer with the kind of slow process in which justice is dispensed with now and *Gram Nyayalayas,* would by their very nature would function as fast track courts and not fall in the same trap of delaying cases for a long time. It is a welcome Bill. But it has its own pitfalls. This Bill can fall in the same trap of *court/Kacheri* system of delays and slow speed. Conflict resolutions and general agreements that are made through revenue officials will now reach village courts. So, I think, the hon. Minister will take note of some of these things and tell us on how the *Gram Nyayalayas* are going to function effectively. In no way should it become a kind of system where again it fails due to bias at lower levels. There was reference to the functioning of Panchayat system also. I understand that the Panchayat system has emerged a successful system in India and yet, there are problems. There are dalit Panchayat Presidents who are finding it so difficult to run their Panchayats. And there were cases where Panchayats meant for dalits could not hold elections for some time. We ought to fight and even now there are problems at that level. That is why, when we set up such Gram Nyayalayas, we should always be cautious. We are a system, we are a society, where we have all kinds of prejudices and conflicts. These Gram Nyayalayas should be above all this and its primary concern must be only to deliver justice to the poor, toiling people, and they are kept away. I don't want to explain the difficulties of poor people, how they suffer when they get into some cases. Now is the time to ensure that they get justice and that justice is not delayed or denied to them. With this aim this Bill should be considered.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, I am grateful for your kind indulgence. I dare not criticise the hon. Law Minister. He is very learned and erudite, and as per his own

statement, he has taken every care to draft this historical Bill. But still, I have the honour of making certain other suggestions for his kind consideration.

Sir, I would say, 'देर आयद, दुरुस्त आयद'. Since the adoption of the Constitution in 1950, we are now taking note of Article 39A; 58 years have passed since then. The Article said that equal justice and free legal aid must be provided to the poor. Anyhow, the day has gone and credit has gone to the present Law Minister who has had three consecutive terms, and we wish that he gets the fourth one also. It has taken twenty-two years to implement the 114th report of the Law Commission, and one-and-a-half years have gone by since this Bill was introduced on 15 May, 2007. As far as objectives are concerned, they are very laudable. But, as they say, 'the way to hell is paved with best intentions'. I wish whatever is expected of this Bill proves true. Only history and time will pass this judgement. There is no denying that fair, speedy and affordable justice is the need of the hour. It is the fundamental duty of the State to dispense justice and it is the fundamental right of the citizen to get justice. इंसाफ पाने का अधिकार गरीब से गरीब को हो; that should be the dream of any legislator and I think that is the objective of this Bill. But concerns have been expressed by Shri D. Raja, Shri Lalit Chaturvedi and certain other very distinguished MPs here. Two concerns have been expressed— Will we not be creating a new holy cow or will we not be creating a new class of white elephants? What will be the difference between *Nyaya Adhikaris* and ordinary Magistrates, which are in a taluka or in a block? There is hardly any block in the country where there is no existing judicial system. Now one more tier will be added and they will be called *Nyaya Adhikaris*. The word '*Adhikari*' is a very dangerous word for villagers. It creates terror; it creates separation from common man. Could we have some better word like *'Nyaya Sahakari'* or something like this? It is just a suggestion. There is not much in name as Shakespeare has said, "You call rose by any name it smells sweet." So, it is up to the hon. Law Minister to think about it. But basic aim of any new legislation should be how to make village litigation-free. If litigation is there, curse is there; if litigation is there poverty is there because in litigation, ultimately, nobody wins because one who wins is like dying over the dead. How to make village litigation-free? In this context, I think, what Ms. Sushila Tiriya has said about basic law system or justice dispensation system at grass-root level in tribal areas is true where villagers collect together; they really know the truth what it is. They may not know legal jargons, but they know what has happened and that brings out the truth when there is an assembly. Same experiment has been tried by Nanaji Deshmukh, that *Raj Rishi*. Let us keep him above politics. In Chitrakoot a very strange experiment has taken place, a revolutionary experiment has taken place where a cluster of villages, about hundreds of them, are totally litigation-free. They consider and settle their disputes amongst themselves. That has been reflected in this Act also. The ultimate objective is a conciliatory system between the parties. That should be the real crux and aim of the new judicial system. I don't know whether it would be possible to ensure that this

intermediary tier of village *Nyayalayas* will ensure that it is not anti-poor and pro-rich, that it is not costly, that it is not pro-*status quo*, that justice cannot be bought and there is no corruption. Insulation to this new institution from two curses — curse of money and curse of muscle power — must be ensured somehow. I don't know what provision can be made. Another submission was: Could we do without advocates? Advocate is a person who gets his pound of flesh from both the parties. I had been advocate myself; there are so many advocates here also. At village level, at least, let there be no advocates in these courts. That is my submission. If advocates are there, then the expenses must be totally paid by the States and not by the parties. Only then the poor will be benefited, the last in the row, *Antayodaya*, will be benefited and objective of this laudable Bill will be achieved. I thank the hon. Law Minister for not interrupting in between and pointing out my lapses, which I think are many, and I thank him for bringing out a utopian Bill. Hopefully, it will bring justice to the doors of the poorest of the poor without hassle, without cost, without bother and that will be a dream not of only Chanakya, but of Father of the Nation, Mahatma Gandhi. Thank you for your kind patience.

**श्री राजनीति प्रसाद** (बिहार): महोदय, यह जो ग्राम न्यायालय विधेयक है, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय कानून मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस शब्द से शुरू करना चाहता हूँ कि "जब ही जागा तब ही सबेरा"। साठ साल बाद माननीय कानून मंत्री को या समाज को या देश को यह बात याद आई कि Civil Courts या Sub-division Courts में जो कानून है, वहां पर जो law है, जो कानून है, It is a paradise of lawyers, जिसको खत्म करने का काम उन्होंने किया है। मैं इसके लिए उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब कोई कानून बनता है, तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन जब कानून बनते हैं, तो उनमें amendment भी होते हैं, इसमें भी अभी amendment आएंगे और बाद में भी आएंगे और यही practical approach होता है। मैं खुद एक वकील हूँ और मुझे 36-37 सालों को अनुभव है। एक साधारण से बैल की चोरी के केस में एक गरीब आदमी को थाने में पकड़ कर लाया जाता है और फिर उसे शहर के सिविल कोर्ट में लाया जाता है। अभी तो कुछ सब-डिवीजन भी बढ़ गए हैं, जिले भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जब यह नहीं था तो एक बैल की चोरी में, फसल की चोरी में, गाय की चोरी में एक गरीब आदमी को पकड़ कर लाया जाता था और उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में appear किया जाता था। वहां पर lawyers होते थे, पैरवीकार होते थे, दलाली वाले होते थे कि तुम्हारा जमानत करवा देंगे, उनको जमानत की भी तकलीफ होती थी कि उनकी जमानत कैसे होगी। माननीय कानून मंत्री जी ने इसको थोड़ा खत्म करने का काम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा खत्म नहीं हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि गांव में जो कोर्ट जाएगा, गांव का मतलब गांव से नहीं है, बल्कि जो ब्लॉक के स्तर पर है, उसमें जाएगा और वहां न्यायालय बनेंगे। वहां तो पहले से ही कोर्ट की व्यवस्था है, क्योंकि वहां तो बहुत-से systems हैं, वहां बहुत-से रूम खाली रहते हैं, उसमें आप न्यायालय बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम conciliator भी बहाल करेंगे, यह उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे शिवानन्द तिवारी जी, जो कि एक अच्छे वक्ता हैं, ने कहा कि पंचायत में तो ये सब पहले से होता ही था, तो नया कानून बनाने की जरूरत क्या है। यह पंचायत में होता था, लेकिन यह जो 379, 380 और जो भी कानूनी provisions हैं, उनके अंतर्गत जो लोग पकडे ज़ाते थे, तो उनको पंचायत में नहीं रखा जाता था, बल्कि उनको कोर्ट में लाया जाता था। जब कोर्ट में लाया जाता था, तो procedure कोर्ट का होता था। उसमें गवाही होती थी और गवाही होने के बाद उसमें उसको सजा होती थी। ये सब provisions तो इसमें भी हैं,

लेकिन ये सब सुविधाएं उनको गांव में ही मिलेगी, ब्लॉक में ही मिलेगी। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है, वह यह है कि आपने एक अच्छा काम किया है, चूंकि मुझे याद है कि पहले जब हम लोग gown पहन कर जाते थे, तो लोग बोलते थे कि बिना gown वाला बहस जज सुनता ही नहीं है। हम लोगों को अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलनी पड़ती थी कि हम ज्यादा बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, कानून संगत बोल रहे हैं, यह बात नहीं थी, बल्कि हम पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि अंग्रेजी में जजमेंट भी नहीं लिख सकते हैं। जब आप जजमेंट हिंदी में लिखेंगे या प्रादेशिक भाषा में लिखेंगे, तो जो lawyers होंगे, उनको भी उसी भाषा में बोलना पड़ेगा, इसलिए वह paradise नहीं होगा। हम लोगों की एक अच्छी सी मांग भी थी कि "अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा।" तो आपने उसको कर दिया है और किया ही नहीं, बल्कि कानून बना दिया है कि जजमेंट जो होगा, वह ऐसा जजमेंट होगा कि दोनों पक्ष के लोग उसको पढ़ सकें। रीजनल लैंग्वेज में होगा, दोनों पक्ष के लोग उसको पढ़ सकेंगे। इसलिए सर, मैं बहुत उम्मीद के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह जो कानून बना है, गरीबों के लिए जो बिल आया है, इसलिए नहीं कि उनको ज्यादा सज़ा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि उनको साइको है कि उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको शहर जाना पड़ेगा। इसलिए उनका जो साइको फीयर था, उनको उस साइको फीयर से इस ग्राम न्यायालय में राहत मिलेगी, इसलिए मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कई लोगों ने कहा कि अब नैचुरल जस्टिस तो vast है, नैचुरल जस्टिस को कैसे आप करेंगे? Evidence Act लागू नहीं होगा। हमारे अहलुवालिया जी ने भी कहा कि यह जो summary provision है, वह summary provision तो है ही यहां पर, तो आपने क्या कर दिया? Summary provision तो है, Cr.P.C. में तो summary provision है, चोरी के लिए summary provision है, लेकिन उसमें कितना दिया है? 380 में, 379 में, 381 में summary provision हम लोगों को दिया है। इन्होंने कहा है - बीस हज़ार रुपए तक का summary provision होगा और मैजिस्ट्रेट trial करेगा। सर, गांव में गाय की कीमत बीस हज़ार से ज्यादा नहीं होती है। पांच हज़ार, दस हज़ार, पंद्रह हज़ार होती है। सर, इसमें एक खूबसूरत बात है और खूबसूरत बात यह है कि अभी जितने भी हम लोगों के लिए आपने laws बनाए हैं, चाहे वह परिवार न्यायालय का हो, चाहे वह और भी जहां हमारे grievances होते हैं, हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, वह खराब सामान देता है, तो उसमें भी हम लोग जाते हैं, वहां भी है, तो decree के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। अगर वह कानून बना दिया, आपको फैसला दे दिया, लेकिन decree के execution के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, तो यह इसमें नहीं है। यह बहुत अच्छा काम है और आपने कहा है, हमारे एक साथी ने कहा कि सैशन कोर्ट में तो बहुत सारे बिल हैं, तो आप अपील करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसमें यह लिखा है कि छः महीने में आपको अपील का पूरा खत्म करना पड़ेगा। अब हमारे यहां अपील की व्यवस्था है, और judges appoint हो जाएंगे, और मैजिस्ट्रेट appoint हो जाएंगे, और जो गांवों के वकील आते हैं, क्योंकि वकीलों को आपने रोका नहीं है, जो गांवों से, ब्लॉक से वकील आते हैं, जो remote areas से वकील आते हैं, अब उनको शहर में आने की जरूरत नहीं है और शहर में तो बड़े-बड़े केस, कानून होते हैं, करोड़ों रुपए का मामला होता है, लेकिन छोटा-छोटा मामला जो आता है, एक कट्ठा और एक बीघा का जो मामला आता है, घर के बंटवारे का जो मामला आता है, तब वे कहां जाएंगे? अगर ग्राम न्यायालय रहेगा, तो कट्ठा और बीघा, एकाध कट्ठा और एकाध बीघा का जो मामला आएगा, कभी थप्पड़ का मामला आएगा, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, उसका मामला आएगा, तो उनको राहत मिलेगी। इसलिए सर, मैं आदरपूर्वक हृदय से, मन से कहता हूं कि पहली बार इन्होंने बढ़िया काम किया है और गांव के लोगों को मोबाइल कोर्ट भी दिया है। कई लोगों ने कहा कि मोबाइल कोर्ट में सब गुंडे लोग रहेंगे, तो गुंडे लोग तो सभी जगह रहते हैं, तो उसमें क्या करना है? कोई बोल रहे हैं कि गवाह को डराएगा-धमकाएगा, तो अगर गांव के स्तर पर रहेगा, गांव में अगर न्यायालय बनेगा, तो दोनों पक्ष के लोग रहेंगे, किसको कौन डराएगा-धमकाएगा? इसलिए शहर में अगर

आएंगे, तो उसमें गुंडे लोगों का डर रहेगा, लेकिन गांव में अगर न्यायालय होगा, तो कोई डराने का मामला नहीं आता है। इसलिए कानून मंत्री जी, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आप इसी तरह से हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहिए, तो फिर हम लोगों की पौ बारह होगी, फिर हम लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, धन्यवाद।

**[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]**

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, when I asked to speak and you gave me permission to speak, I prepared myself to speak on the Bill as it was printed and circulated to all the Members. I have been listening to all the speeches made since yesterday and I find that quasi totality of all the Members are under an impression that the Gram Nyayalaya Bill is about establishment of the judicial facility, if not at village level, at an intermediate level, for a group of four or five villages. This was the impression with which hon. Mr. Raut also started speaking. And, when the Law Minister intervened to give certain clarifications to hon. Shri Raut, I find that we are actually discussing two different things — one is, of course, the Gram Nyayalaya Bill and second is, if the clarifications given by the Law Minister are correct, then, the correct nomenclature of the Bill should be block level extension or the proper extension of the adjudicator. Now, the Hon. Minister is talking of establishing courts only at block level which is *taluka* level. I think, there is hardly any State in the country where you don't have judicial facility at the block level. If your calculation is that 7,000 Magistrates are going to do the work, then, you are really not thinking at all of going down to a village or going up to a group of villages. Therefore, I think, I will try to attack both the interpretations of this particular law. As you know, Sir, throughout my public life, I lived in villages and strived to secure justice, a sense of dignity and self-respect for villagers. The ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, how is the mobile phone ringing?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Where?

SHRI S.S. AHLUWALIA: Just now the mobile phone rang up. The point is, time and again, I am raising this issue in the House. ...*(Interruptions)*... One minute, Mr. Darda ...*(Interruptions)*...

**श्री राजनीति प्रसाद** : आपका जैमर काम नहीं कर रहा है।

**श्री उपसभापति** : जैमर बदला था।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Time and again, I am raising this issue. It is a security matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to know whether it is a reminder in the mobile or a mobile call came.

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA (Maharashtra): This is a reminder, Sir.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Reminder of what?

**श्री उपसभापति**: अलार्म होगा।

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, no, earlier also, two days back, Sharad Pawar's phone was ringing here. Some other Minister's phone was also ringing. I raised that issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will check it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a security concern, Sir.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, most of the Members praised the Law Minister as if he was fulfilling the dream of Mahatma Gandhi who said that India lived in villages. Most historians have agreed that despite various invasions and tumultuous history India survived and Indian society survived because of the autonomous institution of the Gram Panchayat in India. Sir, I am afraid that this particular Bill, rather than helping the autonomy of the Gram Panchayat, is actually going to devastate the historical institution of the Gram Panchayat. What would happen is — I am now talking of the first interpretation, that is, on the Gram Panchayat Bill as it was circulated, presuming that there is going to be first class Magistrate and lawyer sent to each village or a group of villages — the first class Magistrate would have come from nearby city to the village, the lawyers would have also come from the nearby city to the village, the police would have brought the prisoner also from a nearby jail, which would be in a district place or a *taluka* place and they would play a certain drama in the village. The only difference would be that the complainant, even in case of criminal cases, would be required to pay the fees of his advocate which is provided for in clause 21. Apart from that, that could have really not meant extension of the judicial system at the Gram level at all. Now, let us come to the interpretation of the clarification that the Law Minister gave that this has nothing to do with Grams; this has nothing to do with villages. It is really only a block level extension. ...*(Interruptions)*... With the ramification that there will be a ...*(Interruptions)*...

SHRI H.R. BHARDWAJ: I have not said that it has nothing to do with grams. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: But you said that the courts would be established only at block level.

SHRI H.R. BHARDWAJ: I have not said this. You are putting words into my mouth.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: You have said it. You can check up the record, Mr. Minister.

SHRI H.R. BHARDWAJ: No. I remember it.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: You said that it would be only at the block level.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is clarifying it.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Okay, Sir. Now, if it is at the block level, the question is: Which are the places where new courts are going to be opened at all? Is this not a hoax in the name of gram panchayat? I think that the Law Minister should take back this legislation and present a new legislation under the title or under the nomenclature 'extension of judicature to the

block level' which already exists. There is nothing in it, and all the praises that were showered on the Law Minister, I think, were entirely uncalled for. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mangala Kisan, you will be speaking in Oriya.

**श्री मंगल किसन** (उड़ीसा): महोदय, ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 का मैं समर्थन करता हूं। मुझे एक बात बोलनी है और सरकार से अनुरोध करना है कि till today, in the judiciary, reservation for judges from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has not been introduced. The people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are far off from the judicial system. They are living in very poor, and precarious condition. They are not availing themselves of the benefits of the judicial system to get the justice. Prior to the Independence of our country, especially the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes were having their separate system; they were having their gram sabha or gram panchayat. Every case of the village was being settled, and justice was given to tribal people among themselves. But after the introduction of new judicial system, it is far from their reach due to their economic condition. They are not even equipped to avail themselves of the benefit of whatever system is available in the country.

When the system of gram nyayalaya is going to be introduced in India, at least, there must be some provision for the indigenous people to have a separate language. One tribal group cannot understand another tribal group's language. Though the pronouncement by judges is written either in Oriya or in Bengali or in Assamese or in Gujarati, the tribal people living in that State don't even know Oriya or other State's language. It is the real condition of our country.

So, when the system of gram nyayalaya is going to be introduced in India, to give justice to the poor people, the indigenous people, the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes, this section or this part should also be considered. Anyway, I hope that the Government of India would also take care of the interest of these people. Though these people are living in India, they do not know anything about the system prevailing in India, not only in respect of the judicial system, but also about other systems. So, the hon. Law Minister and the Government of India must take care of the interest of those people and they should also take steps to determine what type of system should be provided to them to give some benefit to this neglected section of the society in India. I thank you for giving me this opportunity to express my views in this House.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Thank you, Sir. It is a welcome step of the Law Ministry that it has come up with this particular Bill, the Gram Nyayalaya Bill. We, on behalf of the Assam Gana Parishad, must appreciate the steps taken by the UPA Government. We need nyayalaya at our doorsteps. We should congratulate the Government. It has also the bounden duty to strengthen the system which is prevailing in our country, all mechanisms like arbitration, conciliation and mediation, conducting of lok adalats, fast track courts, special court tribunal, providing free legal aid to the poor women and children *etc.* There are some shortfalls in regard

to tackling and making use of the legal services by the masses, specially, the tribals and the backward castes of the north-eastern region. It also suggested that some useful guidelines like an appeal from the judgment and order of the gram nyayalaya in civil cases to the extent provided in the Code of Civil Procedure 1908 shall lie to the district court which shall be heard and disposed of within a period of 6 months from the date of filing of the appeal. It also suggested justice to the poor at their doorsteps which is the dream of the common man like setting up of gram nyayalas who travel from place to place, and this would bring to the rural people speedy, affordable and substantial justice. Sir, it is well-known to all that the remote villages in the North-East are not easily accessible. We take 4 to 5 days to reach some villages from the towns in the North-East. There is tremendous communication bottleneck in the North-East. I would like to know whether the Government will make special arrangement or provide for a mechanism to take gram nyayala to those areas. I would also like to know whether before taking this Bill into consideration, such questions were discussed by the Law Ministry or not. The hon. Law Minister will definitely give a reply to such questions because we are talking about mobile gram nyalayas. On the other hand, we have a perennial flood problem in the States like Assam, West Bengal and Bihar. In Assam, most parts of the State remain under flood water which extends from 5 to 6 months. I would like to know whether it will be possible to hear and dispose of the cases within a period of 6 months from the date of filing of the appeal. It must also be pointed out that the North-East is facing an acute problem of security. I think the hon. Minister will take responsibility to look into this problem and take steps for its redressal. With these few words, I support this Bill.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I would like to refer to what Mr. Anantrao Joshi has said. I will take one minute. I rise, because I want to be an active participant in the great revolutionary movement of the day. Such a great Bill has come up before the House. It is holistic, not that it answers all the problems that came from the humanity to this day. But nonetheless, it is an attempt to take justice to the people for whom the justice is meant. Sir, it is redeeming our promise that we have made on that day when we opted for a Constitution under the Republic. Mr. Joshi perhaps thought that it was an extension of the judicial system. Please let me correct him that in a taluk level judicial system, only lawyers appear. As the Minister was, earlier, telling us in his introductory remarks, about 'imperial legacy'. Only the lawyers could attend the taluka or the district courts. Now, under this system, both you and the lawyers can do so. This is what is known as 'participatory justice'. There is something known as 'the sociology of law'. 'The sociology of law' tells you that unless you blend the system into milieu, the justice cannot reach you. This is what, exactly, is being attempted today. What is attempted, today, is not as simple as what Mr. Ahluwalia said, speedier and fair justice. Anything can come under 'speedier and fair justice'. It is accessibility and also cheap justice. It is a first step towards that. As a matter of fact, there is also, some, confusion about what my friend has said, that Mahatma Gandhi's dream should be realised. I know as to what exactly he meant.

He has a view that the Panchayat Raj is yet to be empowered. We have to see what the tribals do even today and how they settle their disputes. This has not been touched. But that was found wanting. What they have done, to the Panchayat Raj, Sir, is that at the same level, for the same type of people, for the same institutions, some kind of judicial power is added here. What was an 'ordered' yesterday has become a decree today. That decree is backed up by some kind of implementing agency known as police, revenue officials and government. So, it is a combination of the two Nyay Panchayats and Gram Nyayalays. It is, actually, an integration of the two. That is exactly is the sociology of law. I am not trying to talk about the law at the district level or at the High Court and the Supreme Court levels. Leave it at that. If you want to take law to the people, try to understand its nuances, try to understand their proclivities and try to understand them first. That is exactly what they are trying to do. Let the people have a reach to the law. And the law is now reaching them. As somebody is saying 'legal literacy movement', Sir, you can tell people as to what exactly their powers are and whether there is any agency readily available next door, where they can go and knock that door. That is exactly what is being attempted today. It is not only an attempt towards the fulfilment of the democratic promise that you have made, it is not only an attempt towards the fulfilment of people's urge that is feet, but it is an attempt towards the evolutionary process of a democratic polity that is being attempted. We have tried to open all these doors. I want to congratulate the hon. Minister here, whom I have known since long; I know him for his commitments. I know him from the days when our leader Smt. Indira Gandhi committed herself to the poor, from the *Garibi Hatao* days. And this, I think, is a part of that Committment—Bill that you have brought in. I would, rather, stand corrected. But, at the same time, let me tell you what my friends have said, what Mr. Ahluwalia has said. There are few things which should be revisited. But that should not stop us from going ahead with a revolutionary idea. The greatest fear, the worst fear in the mind of a man, is apprehension. All these apprehensions will, automatically, get solved the moment we cross the bridge. As we go ahead, as one of my learned friends said, we will have notifications. I think fifty per cent of our apprehensions—that my friend has raised and that the others have raised — will be solved through it. The solution is there. As regards the certain problems which have been mentioned in one of the clauses invoked by the Centre and the States, they can have a look at that and amend the same at appropriate time. Again, there is a House like ours. Whenever an amendment is required, it will be placed before us. We will look into that. Once you have got some experience, for example, about 'right of property' or, let me say, the 'farm houses' or, let me even say, the 'defamation', all these and few other things. There is an 'Appeal' provision. I want to remind my friends, that there is an appeal provision. The moment the appeal provision is available. The bitter experience is brought to the notice so much so that we would be able to sort it out. Let us all welcome this measure more as democrats, more as persons who are committed

5.00 P.M.

to the people, because we come here to this House in the name of people all of whom we have not perhaps seen. At least, three per cent of the people live in the tribal areas, whom we have not seen and whom we cannot reach — tribal tracks. But, at the same time, we should not come in their way. Let us think together that when a Government or any agency is trying to take justice to their doorsteps of the people it that should be welcomed. It is the duty of the Government and also of my party because to undertake midcourse corrections. The Government job is over. The duty of Parliamentarians like us begin today because we have to tell the people that there are certain institutions known as Gram Nyayalayas available to them, both as judicial units and certain conciliatory methods. This is participatory justice that we are talking about as against the administrative justice which the Britishers brought in. The British legacy should end today. So, I welcome this Bill. I, once again, on behalf of all the people, congratulate this Government and the UPA from the core of my heart. It has started this and made it into a reality what we have been thinking for the last 22 years. It is not only the 114th Report of the Law Commission but also the 54th Report of the Law Commission, the 58th Report of the Law Commission and many other Reports of the Law Commission that have talked of reforms in law and in the procedures. I am not going into all those things. All those things will be solved. I am not saying that at one stretch we will be able to solve those things. But let us go ahead and this will be a dream come true in the very near future. Thank you.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, I want to know one thing. I would like to know whether these courts will also have the safeguard of contempt.

SHRI H. R.BHARDWAJ: Hon. Deputy Chairman, Sir, I am deeply grateful to all the hon. Members who had taken very keen interest and kept the debate on this piece of legislation at a very high pedestal. It is the tradition of Parliament, when we discuss about justice administration or anything regarding the Judiciary, the House always speaks in one voice because the Judiciary does not speak for itself. It speaks through us. I am very grateful to the hon. Members because, by and large, they have supported this Bill and gave their frank opinion also.

Sir, it is the job of the Parliament to discuss every issue threadbare and then, out of the debate, emerges the knowledge which purifies the mind of the Minister. I am very grateful to all the speakers, in whatever spirit the suggestions have been made, and I will quote from Tulsidas' Ram Charita Manas, "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"... So, I see it from one angle. How to help the people? This is a divine function. Administration of justice is a divine function. My friend, Shri Ahluwalia, is a very knowledgeable MP. Besides that, he is well read. He started with Kautilya. But let me remind you that we are an ancient civilisation, in vedic civilisation. We had a very ancient Sanatan Dharma also. There the principle of natural justice was prevalent in olden days. The principle of natural justice is "सत्यमेव जयते" ... So, we are for civilisation.

But you know that in dark days we lost our freedom and remained under various regimes historically and we regained freedom from them. When we had the Mughal rule, we had a different system. The present revenue system still continues from that period and all the criminal courts in the country function according to that system. Every word we write in criminal cases are from that period. Words like ज़ाब्ता फौजदारी, मुख्तसर हालात मुकदमा, दीवानी are all from that period. After that, the English people came. They set up the first court at Fort William in Calcutta. But soon they discovered that India is a country with so much diversity. There is no uniformity in the judicial system. I remember the famous words of Lord Macaulay and Stephan when they started codification during the debate on Charter Act, 1833. They asked, "How to draft law for India because every State has different law, different courts. All Rajas and Maharajas have different courts and different system of administration of justice"? They said, "We would adopt the principle". They also studied Kautilya extensively. William John, who was a judge in Calcutta, was a great scholar of Indian scriptures. He is remembered by all of us. He established the Asiatic Society. William Jones, Wilkins, and others are the famous English names in our history. They contributed a lot. We should be grateful for that. They said, "We will give to India, as far as possible, a uniform system of justice". So they created uniformity in courts; magisterial courts, session courts and high courts. They said, "We will give uniformity and certainty to India wherever it is possible". They codified the Indian Penal Code, which is a composite law containing all eventualities or offences. They gave the procedural law and the evidence law. It took 50 years for them to codify this. That was very good. We have carried on. In the first Law Commission, they were examined. But the fact remains that in India changes have not come in just one period. In India, changes have come in each period, slowly and steadily. Today, we are republic of over 50 years. Our founding fathers were great and wise people. They gave human liberty and civil liberty and so much. Besides what the Criminal Procedure Code said, they enshrined in our Constitution the Fundamental Rights. We have to be careful when we do something in the matter of judiciary.

Some Senior Members are very keen to have Nyaya Panchayats. Shri Ahluwaliaji raised discussion with my colleague, Shri Mani Shankar Aiyar. We all are friends. I dealt with the Panchayati Raj in my first tenure. In this very House, I piloted this Bill. People snatched papers from my hand. They did not allow the Panchayati Raj Bill to be enacted. I remember it. Where is the consensus on Panchayats getting powers of judiciary? Do you think anybody in the House will vouchsafe that Panchayat courts would be acceptable to all of us? There is a difference of opinion. In no case the quality of justice should be compromised. When you talk of poor people, you give them to the Panchayats and when you talk of elite, you want that they should be governed by regular courts. That is not possible. We have to keep the quality of justice uncompromised and of high standard. We are proud as a country that after Independence we have a wide network of courts. I agree; when I started my practice, there was one session judge

for three-four districts. He used to go in circuits. But today there are several session judges and dozens of magistrates in one district. Still the pendency in courts is increasing. Yesterday, you grilled me for one hour on this issue. Let us be sincere in regard to this cause. Sir, I have a consensus of the nation with me because we have held joint conferences with Chief Ministers, Chief Justices and the Prime Minister, discussing the issue of arrears and how to improvise the system. We are proceeding in that direction. I have consulted the Law Ministers of States twice. Once in Shimla and secondly in Hyderabad and then in Delhi. They all agreed that the changes are necessary, but not radical changes. Shri Adhikary, who is Law Minister of West Bengal and my best friend, said, "You must come to West Bengal. We are doing something radical." I travelled there, participated in the Seminar, and they were bringing a very good law. They were establishing 'Block Level Conciliation System'. Unfortunately, one day, I found that he could not do it. If you want radical changes, be prepared for it; persuade yourself and bring consensus. But I supported that because the conciliatory system was in our ethos. In fact, there is one cloth market, the Hindustan Merchantile, in Delhi; they don't go to do litigation. There is one place at Ahmedabad. They too do not do litigation because the members have decided that they would solve things amongst themselves and help one another. If that can be done, then, I will be the happiest person. There will be no crores of pendency of cases. But, today, the situation has come where everybody wants to litigate, and they enjoy litigation. This is the position. And, there was a docket explosion.

Then, Ahluwaliaji referred to Judicial Manpower Report. Yes; the same Law Commission, headed by Shri Dhirubhai Desai, — a radical judge from all standards; he is also from Gujarat — gave this Report. And he suggested that we should improve the manpower ratio per million population. The matter was again put before the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices, and they came to the conclusion saying, "We will not be in a position to improve beyond a certain point unless the Centre comes to our help." The Central Government does not have the responsibility of trial courts. Under the Constitution, the Centre's responsibility is not to build courts in the States. Yet, as it relates to administration of justice, we agreed, in my earlier tenure, when I was the Planning Minister, to share 50-50 in judicial infrastructure, and persuaded the then Deputy Chairman, Shri Pranab Mukherjee, to ensure it that Judicial Courts were decent and the judicial houses are built. We started our project, but it was inadequate. In the British regime, a Court was built. At that time, there were 10 lawyers in India. A few lawyers were there in a district in the olden days. But, with the spread of democracy, knowledge and education, now, there are over a million lawyers in the country and over at least a thousand lawyers in each district. In Delhi alone, there are 20,000 lawyers. So, the number of lawyers has increased. The litigation has increased. We want judicial manpower. So, some way has to be found in this situation. We also wondered whether we could change the procedures. I am not fascinated by

the procedures of the 19th century. I read a very beautiful line from Michael Kirby, an Australian Chief Justice. He said: "Beyond the magistry of the English procedures, there is a lurking shadow of miscarriage of justice" He always remembers that we stick to these codes and procedures. People don't understand these procedures. People say, "We want quick justice." People say, "We want inexpensive justice." So, it is for all of us to see that they do get this. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sometimes, 'Justice hurried is justice buried. The other way round, 'Justice delayed is justice denied'. These are the sayings of the learned people.

SHRI H.R. BHARDWAJ: My dear friend, I started by saying that in matters of justice administration, you cannot do things hurriedly, and, you cannot also delay because justice delayed is justice denied. So, you have to go in between. Therefore, India is treading safely. India is one country which has so much of rich experience because Members of Parliament belong mostly to the legal profession. And some of our freedom fighters also were highly learned advocates. So, we are treading safely. In Nehru's time, there was a resolution by Shri N.C. Chatterjee, and he wanted a drastic change. Shri Seethalwad dealt with that issue and came to the conclusion that we could modify the existing edifice; this is quite good. And I agree, respectfully, that after setting up such wide networks of courts in the districts and *talukas*, can you disband them and start overnight a new system? In the comity of nations, in the Commonwealth and elsewhere, India is praised for these institutions, for our democracy, and for our rule of law. Who will sustain the rule of law, if there is a weak Judiciary, and a frustrated Judiciary? That is why we decided — I persuaded the hon. Prime Minister — that let us go out of the way to accommodate the States in this matter. So, it was agreed that the Centre should extend the Fast Track Courts started by the Vajpayee Government, and it proved that out of 28 lakh cases, we have been able to wipe out 21 lakh cases by these Fast Track Courts by this date. So, it is a good experiment, although it is not a permanent solution because after 2010, either it will be extended, or, it will be stopped. So, this is another measure. It is not a solution completely of the problem. But, if this is carried on in this spirit of the Centre and the States sitting together, then, it can succeed. Let me tell your Ahluwaliaji, no legal system has been evolved overnight. The Britishers struggled for centuries, from the Magna Carta to the Parliament, and this Common Law was built over centuries with the help of lawyers and judges. That is why there is a completely successful legal system in England. Since they are a theocratic State, they don't have any other problem. They are a conservative Christian State. So, they swear in the name of the God, and they stand by that. But, we swear in so many names and we don't stand by it. That is our difficulty. ...*(Interruptions)*... But, I tell you we are a democracy. We will do it slowly and steadily. In the end, India will win the race. You will see that in the next five years, Indian Judiciary will be on the top of the world. I will enumerate here and now how the Indian Judiciary will be on the top of the world. We are starting the first step. I have the figures

from the concerned Ministry that in India, there are 2,32,088 Gram Panchayats; there are 5,067 Intermediate Panchayats and there are 536 *Zila Parishads*. This is the statistics I got from the Panchayati Raj Ministry. So, I am not saying that there will be 2,32,088 figures. I am saying that we can accommodate 5,067 Intermediate level Panchayats. So, the States want, we can fund these 5,000 courts from the Centre 100 per cent on capital account, and 50 per cent of their recurring expenditure for a certain period. It will involve thousands of crores of rupees of expenditure. But, the cause is very noble. The hon. Prime Minister has been very generous, despite difficulties. You know, in finance, it is very difficult to get money. But, we have succeeded for a noble cause. That is why there should be no confusion in anybody's mind as to what is the quantum of courts that would be there. It will be below 5,607, at the moment, unless you extend it further. What is the cost calculated for these courts? For that also, I have made a study with the help of High Courts. The average salary component of a Magistrate First Class, and I am very, very sad that people don't understand that the *Nyaya Adhikari* is just a Judicial Officer. Why do you read motives in it? पहली बार हिंदुस्तान में मैंने एक हिंदी का नाम यूज करना शुरू किया, नहीं तो कानून में हिंदी को कौन पूछता था? पहली बार मैंने न्याय अधिकारी नाम सुना है, देखा है। इस से अच्छा और कोई नाम हो तो वह रख देंगे, लेकिन यह हिंदी में पहली बार हुआ है। भाषा के बारे में मैं आप को बता दूं कि हिंदुस्तान के लोग clients particularly, जिनके मुकदमे होते हैं, उनको कोर्ट में क्या हो रहा है का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि वह लेंगुवेज ऐसी होती है, जो वकीलों को ही आती है। चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे बंगाली हो, जानने वाला हाथ जोड़कर कोर्ट में ऐसे खड़ा रहता है। मैं पचास साल से वकालत कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। अब वह फीस देने के लिए किस प्रकार से पैसा जुटा पाते हैं? वह सब आप कोर्ट में जाकर देख लो। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी कठिनाइयों को हम उनकी भाषा में समझ लें। हमने मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश दिए हैं कि अब अगर हम गांव की बात कर रहे हैं, तो उनकी भाषा में ही जाकर उनसे बातचीत करो, गवाही भी उन्हीं की भाषा में लिखो। इस तरह का विचार पूरे देश में एक गरीब आदमी को तो आएगा, लेकिन एरेस्टोक्रेट जैसे लोगों को नहीं आएगा। जरूरी यह है कि लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि हमारी बात कोर्ट तक पहुंच गई है, हमारे वकील ने सही तरह से समझा दी है और जो निर्णय हुआ है, उसमें यह साफ लिखा है। मेरा ख्याल है, हमारे देश के लोग सब्रवादी हैं और अगर उनको यह बात समझ में आ गई कि मेरी बात जज ने सुन ली है और निर्णय सही है, तो अपील भी नहीं करेंगे। लोग सब्र कर लेते हैं।

महोदय, हमारे लोग ऐसे सच्चे लोग हैं, उनके लिए कुछ करें, तो उसमें कौमा, फुलस्टॉप और टेक्नीकल ओब्जेक्शन हमको नहीं लगाना चाहिए। हमने भारत में सारी उम्र इस उन्नीसवीं शताब्दी के कानून को शिरोधार्य करके इसमें अपना कोई एडीशन नहीं किया। पहली बार मैंने प्रोसीजर को मोडिफाइ किया है। मैं प्रोसीजर को इतना महत्व नहीं देता, I know what are the components of a fair trial. जब मैंने कहा कि हमारे आदिकाल में नेचुरल जस्टिस दिया जाता था। जब राजा-महाराजा बुलाते थे, आप फिल्मों में भी देखते होंगे, हाजिर करो, तो वादी को और प्रतिवादी को ले आए, वहां पर एक न्यायाधिकारी भी होता था और वह उनको सुनकर वहीं पर फैसला कर देते थे। उस फैसले पर लोग कहते थे कि ठीक है। इसी तरह से फौजदारी का भी, कि गवाह पेश करो और उनको सुनकर वहीं फैसले हो जाते थे। हमारे देश में जहांगीर का न्याय मशहूर है, अकबर का न्याय मशहूर है, हरिश्चन्द्र का न्याय मशहूर है। यह सारी चीजें इस देश में मौजूद थीं, लेकिन अब हम बाहर के कैप्सूल खाते हैं। इसलिए मैंने इसमें अपने देश का यह इनपुट डाला है कि जहां तक प्रोसीजर का सवाल है, हर आदमी को अपनी बात कहने का, बात सुनाने का और समझाने का मौका दिया जाए। वहां जितने

लोग खड़े होंगे, सबको वह भाषा समझ में आएगी और उनको लगेगा कि सबकी बात सुनी गई। आप सब जानते होंगे, जो गांव से जरा भी ताल्लुक रखते हैं, कि गांव में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, आमने-सामने कोई झूठ नहीं बोलता। आप उससे पूछिए कि यह जमीन किस की है? तो गांव का आदमी कहेगा कि सच्ची बात तो यह है कि यह जमीन इनकी है, इनकी नहीं है। इससे सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चा वादी और सच्चा प्रतिवादी गांव में है और गांव में फिर आंख मिलाकर वे लोग भी झूठ नहीं बोलते। इस प्रक्रिया से यह चीज होगी कि जब मजिस्ट्रेट वहां जाएगा, यह मजिस्ट्रेट मैंने इसलिए बोला कि बहुत लोगों ने कहा कि पंचायत में पंचों को और सरपंचों को पावर दे दो, मैंने पहले देखा है, जब मैंने वकालत शुरू की थी, तो उस समय पंचायतों को पावर थी फौजदारी की भी और दीवानी के फैसले की भी, मगर सरकारों ने इस तजुर्बे के बाद कि सही न्याय नहीं हो रहा, इसे विदड्रा कर लिया। अब कहीं कोई ऐसा बचा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी मैं अपने तजुर्बे से यह नहीं समझता हूँ कि यह अधिकार पंचायतों को दिए जाने चाहिए, इसीलिए मैंने मणिशंकर अय्यर जी की इस बात को नहीं माना। उनके काफी लोग हैं, उनकी एनजीओस हैं, जो अभी भी मेरे पास आते हैं कि आप कर दो। हमने कहा कि गरीबों के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, गरीबों को भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देंगे।

कन्सीलिएशन में, जो कन्सीलिएशन है, वह हिंदुस्तान की इथोस में है, वह हमने डाल दिया है कि गांव में कन्सीलिएशन हो। जैसे वेस्ट बंगाल में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कन्सीलिएशन सेंटर खुल रहे थे, तो हमारे यहां भी हो जाएं। वह अच्छी चीज है, उसमें किसी का खर्चा नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी। उसके बाद हमने आगे जाकर यह कहा है, यह टेक्नीकल बातें जो कही गई हैं, इसको पूरा पढ़ना चाहिए। आप इसकी इसलिए अनदेखी मत करो कि मैंने इंटरोड्यूस किया है। यह आपका ही बिल है। यह देश की धरोहर है। मैंने क्लियरली लिखा है कि a Panchayat Adhikari shall visit villages. इस विधेयक द्वारा मैं गाँव में न्याय अधिकारी को द्वार पर भेज रहा हूँ। आज क्या हालत है, वह मैंने बता दिया कि लोग गरीब के सामने कुर्सी से उठकर नीचे ही नहीं आते। मैंने इसकी pilot project दो सालों से चला रखी है। पूरे मेवात में मैंने मोबाइल कोर्ट भेजी है, सब लोग आ रहे हैं, कोई ळागड़ा नहीं है और फैसले हो रहे हैं। वहाँ पर एयर कंडिशंड बसेज़ हैं, उनमें जज जा रहे हैं, स्टाफ के लोग जा रहे हैं और पुलिस आ रही है। सारे केसेज़ में आपने कॉग्निजेंस के बारे में पूछा था, तो cognizance in criminal cases will be taken as is being taken today either on a police report or on a complaint and there is no dilution of any procedural law, but what is there in a summons trial or a warrant trial or a sessions trial, these are only names. What is the component of a fair trial? Component means, the man must understand, the grey man must know the charge against him and must know what is evidence that is being produced against him and he should be given full opportunity to cross-examine the witness and say his things before the court. What more do you want in a fair trial? These are techniques of a fair trial which have been strongly built in this law.

भाषा का परिवर्तन और भाषा समझ में आने वाली, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कई राज्य सरकारों से प्रस्ताव आ रहे हैं कि हाई कोर्ट लेवल पर भी होना चाहिए। यह अभी तमिलनाडु से आया है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। वह समय चला गया कि जो अच्छी क्लासिकल लैंग्वेजेज़ हैं, उनकी आप अनदेखी कर दें। उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इस प्रकार जहाँ-जहाँ कोशिश हो वहाँ पर अपनी जो लोकल या रिजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए और राजभाषा देश की ..**(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA: There is a strong demand for it. ...*(Interruptions)*...

SHRI H.R. BHARDWAJ: I supported the West Bengal's radical law but this country did not accept it. If you had accepted it, I would have implemented it in the whole country. ...*(Interruptions)*... ADR is in your access. ...*(Interruptions)*... पंच परमेश्वर क्या चीज़ थी? उसमें

पांच लोग होते थे और वे लोगों को बुलाकर फैसला कर देते थे। ...(व्यवधान)... अगर आप उनकी ही बात सुनेंगे तो फिर इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। आपको गरीब की बात सुननी पड़ेगी, यह मैं आपको कहता हूँ। हमने यह जो बिल लाया है, यह पूरा उसी उद्देश्य से लाया है। अब समय आ गया है कि हम इस न्याय व्यवस्था में इसकी फाउंडेशन को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन, इसकी प्रोसिजरल लेवल पर, एविडेंस पर — आज हमारे बहुत पुराने senior colleagues बैठे हैं। आज आपको एविडेंस एक्ट को implement करने में कितनी दिक्कत है, आपकी जितनी साइंटिफिक है कि यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। अगर आप उन्हीं कानूनों को लिये बैठे रहेंगे — मैंने ओवरनाइट यह इलैक्ट्रॉनिक मशीन लागू की थी। आज आपको उसी वक्त रिजल्ट पता चल जाता है। इस इलैक्ट्रानिक डिवाइस के ऊपर भी मुकदमेबाजी हुई थी, लेकिन हमने पार्लियामेन्ट से इसको स्वीकार करवाया। इससे गिनती कितनी आसान हो गई। दो दिन और रात-भर एक एमपी को जागना पड़ता था, तब होता था। ग्रामीण अंचलों के लिए हमने मजिस्ट्रेटों की यह जो व्यवस्था की है, यह कोई अधिकारी नहीं है, यह पूरा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कैडर है। हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेटों की जो तरक्की और सैलरी-वगैरह है, इनकी भी वही रहेगी। क्या किसी आदमी को मजिस्ट्रेट की नौकरी मिलने से फ्रस्ट्रेशन होती है? उसे तो बड़ी खुशी होती है। पुराने जमाने में अगर लोग किसी से खुश होते थे तो बुढ़िया आशीर्वाद देती थी कि जा तू तहसीलदार बन जा। यह था हमारे गांव में — तैनूं तहसीलदार बनाये पुत्तर! इस तरह यह तो तहसीलदार से बड़े हैं और इनका बाकायदा मैंने दिया है कि The Government of State and the High Court, both will remain in touch for their salary, for their promotion, for their functioning and discipline. तो किसी प्रकार से भी उनकी ज्युडिश्यिल इंडिपेंसी के साथ हमने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कई लोग मुझे कह रहे थे कि दो lay judge इसमें लगा दो और वह जस्टिस देसाई की रिपोर्ट में भी था। मेरा तजुर्बा यह है कि कोर्ट्स में lay judges को भेजना ठीक नहीं है। Lay judge का मतलब क्या होगा? चलो हम करा दें इस काम को। तो उन आदमियों को मैंने इसमें काट दिया है। सिर्फ ज्युडिश्यिल स्टाफ, जो पांच आदमियों का है और उनकी भी salary calculate करके यह 6.40 का एक कोर्ट का expenditure है। इसको multiply कर लो कि कितना होगा, पांच हजार बनाएं, चार हजार बनाएं और यह राज्य सरकारों पर है। अगर मध्य प्रदेश में ग्रामीण न्यायालय काम कर रहे हैं तो वे नए क्यों बनाएंगे, अगर उनका काम चल रहा है। अगर उनको जरूरत है 50 की तो 50 ले लेंगे, अगर उनको जरूरत है 100 की तो 100 ले लेंगे। तो मैंने इस बिल में प्रावधान रखा है कि हर स्टेट का अलग नोटिफिकेशन होगा। मैंने ट्राइबल अंचलों को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, क्योंकि उनका सिस्टम आज भी सच्चा है, वे सच्चे लोग हैं। उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वे जाकर मान लेते हैं कि हमने यह किया है और दीवानी मामलों में तो वहीं पर उनकी पंचायत फैसला कर देती है। जहां पर काम ठीक चल रहा है, वहां मत करो, लेकिन जहां arrears बढ़ रहे हैं, जहां पर कठिनाई है, राज्य सरकार की आर्थिक कठिनाई है, वहां इससे जरूर मदद मिलेगी।

मैं फिर एक बात बता दूं कि मैंने आपका भाषण और आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है। 262 में ही Summary Trial, Magisterial Court का लिखा हुआ है upto two thousand rupee. I have only modified the monetary aspect twenty thousand. वह इसलिए कि भैंस चोरी का केस है, बैल चोरी का केस है, गाय चोरी का केस है, तो उसको इस level पर रखो कि गांव के जो offences हैं, वे इससे cover हो जाएं, नहीं तो फिर यही होगा कि चूंकि यह दो हजार का है, तो दो हजार में तो बकरी भी नहीं आती है। इसलिए इसको practical level पर रखा। घोड़े हैं, लाखों रुपए का घोड़ा होता है, वे भी नहीं आएंगे और मुझे अख्तियार है इस चीज का कि अगर Central Government बाद में चाहे तो किसी section को निकाल दे और नए को लाकर डाल सकती है, लेकिन इसम कोई मर्डर केस नहीं डाल सकते, वही डाल सकेंगे जो छोटे offences हैं। इसमें 100 रुपए के maximum खर्चे का प्रावधान है कि 100 रुपए से ज्यादा टोटल खर्चा नहीं होगा। 100 रुपए इसलिए रखा है कि कोर्ट फीस की जरूरत नहीं है, सिविल सूट कोर्ट में, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैंने इसमें यह भी दिया है कि गरीब का प्रोविजन Legal Aid Authority करेगी। देश में National Legal Aid Authority बन चुकी है - NALSA और हर महिला का, हर scheduled caste सदस्य का, हर बच्चे का और हर परिवार

का, जिसकी आय 20,000 रुपए महीना से कम है, उसका legal aid अधिकार बन चुका है। इस देश में जानकारी के विषय में मैं मानता हूं कि legal awareness नहीं आई है, क्योंकि यह बड़ा देश है। छोटे-छोटे मुल्कों में तो एक बार television पर दिखाओ वह सारे लोगों तक पहुंच जाता है। जिन लोगों ने पहले legal aid का movement चलाया था, हम उनमें से एक वकील थे। हमने जगह-जगह किताबें छपवाकर बांटीं, लोगों को घर-घर जाकर बताया कि यह आपका अधिकार है, अभी हम सेमिनार भी करा रहे हैं। कुछ देर यह movement रुक गई थी, क्योंकि इसके भी बहुत विरोधी हैं। आप तो जानते हैं कि इस देश में ज्यूडिशियल प्रणाली में दो तरह के लोग हैं एक तो *status quo* में विश्वास करते हैं कि सब ठीक-ठाक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी जेब भरी हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है और दूसरे यह कहते हैं कि दरिद्र नारायण का क्या हुआ। तो हम पार्लियामेंट में जो representatives हैं, हम चाहे धनी लोग भी हों, तब भी हम दरिद्र नारायण के लिए यहां आए हैं, क्योंकि यह हमारे देश के संविधान ने पार्लियामेंट को जिम्मेदारी दी है और किसी को नहीं दी है। इसलिए इसमें कोई पार्टी का या फिलॉस्फी का मतभेद नहीं है। जो जवाब यहां श्री अरुण जेटली देते थे, वही जवाब मैं यहां देता हूं और आगे कोई दूसरा लॉ मिनिस्टर बनेगा, उसको भी यही कहना पड़ेगा, क्योंकि देश की प्रणाली कोई एक दिन की नहीं है, आज संविधान को बने 55 साल से ऊपर हो गए हैं, वही कोर्ट्स हैं और मैंने यही इस साल law day पर Supreme Court में कहा है कि India is a proud democracy because there is a strong rule of law in the country. Be you ever so high, you are not above law. मैं पंचायतों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंचायतों के हक में हूं, डेवलपमेंट के काम उनके जरिए होने चाहिए, लेकिन अगर न्याय के क्षेत्र में हम पक्षपात करेंगे, तो कोई मानेगा नहीं, गांवों का गरीब आदमी भी नहीं मानेगा। इसलिए न्याय प्रणाली में मजिस्ट्रेट की मान्यता है, सैशन जज की मान्यता है, वही है इस बिल में और यह तादाद बढ़ जाएगी। इस बिल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने मेरी जितनी तारीफ की है, मैं उसके लायक भी नहीं हूं, I am just an ordinary lawyer. आप लोगों का स्नेह था, इसलिए आप इसे पास करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अहलुवालिया जी ने मेरे आग्रह पर इस बिल को पास करने का मन बना लिया था, इसलिए मैं सबसे ज्यादा इनका आभारी हूं। मेरा और इनका रिश्ता बहुत सालों से है, मैं तो इनको असली पंडित और ज्ञानी, दोनों ही मानता हूं, क्योंकि ये कानून के भी विद्वान हैं और हाउस में जो प्रोसीजर होता है, जो ये प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं, उसके भी विद्वान हैं। हम तो इनसे सीखते हैं। ये सबके विद्वान हैं, इसलिए ये सभी जगह फिट हो जाते हैं, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती ...**(व्यवधान)**...

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: फिट नहीं हो जाता हूं, सबकी जरूरत पूरी करता हूं।

**श्री हंसराज भारद्वाज** : मैं इनका विद्वान होने के नाते बहुत सम्मान करता हूं और जब ये कोई प्वाइंट उठाते हैं, तो मैं उसको तीन-चार बार पढ़ता हूं, हालांकि मैं तो वकालत में Procedural Law का माहिर था, लेकिन मैं देखता हूं कि इनके प्वाइंट्स में बड़ी जान होती है। अच्छी बात है कि ये इतनी preparation करते हैं।

**श्री उपसभापति**: मैं भी इनसे यही कहता हूं कि आप डिबेट में ज्यादा हिस्सा लिया कीजिए।

**श्री हंसराज भारद्वाज**: उपसभापति जी, इन्होंने अच्छी शुरुआत की थी और जब चीज अच्छी तरह शुरू हो जाए और सबका सहयोग हो, तो वह काम अच्छा ही होता है। हमारे यहां तो यह प्रथा है कि दुश्मन के यज्ञ में भी शामिल होते हैं और अगर कोई समझौता नहीं होता, तो DAT को बीच में ले आते हैं कि यह चलाएगा। He is our DAT for the purpose of Parliament.

Sir, I thank you very much for giving me so much of time. I request all the hon. Members to pass this Bill. I also thank the support received from all corners for this Bill. Sir, Bill is for a noble cause. I hope every Law Minister who comes subsequently will have further duties to see that it run smoothly.

Sir, we talk of Gandhiji. He felt only for poor. We have not done enough in the social sector for women, children and poor. We have not done sufficiently for education. Here, in this Bill, I

have made reservation for the SC/ST. I have also made for women. May I read? In all the Bills I am bringing an element of more dynamic role for women. There is a provision in the Bill which says, 'while appointing the Nyayadhikari, representation shall be given to the SCs, STs and women.' They will be appointed by the State Governments in consultation with the High Courts. Here, I mentioned the word 'shall.' Sir, 'shall' means, mandatory. So, I have taken care of you my good friend, Mr. Kisanji. आपकी बात हमने पहले ही स्वीकार की हुई है। इसमें बहुत improvements हो सकते हैं, कुछ add भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपने कही, जैसा कि जस्टिस डी.ए. देसाई ने कहा था कि हमको 50 जज, per ten million population पर रखने पड़ेंगे, इसके लिए हमको उदार दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। यह जुडिशियरी हमारा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है ... यह तो मैं symbolic नाम ले रहा हूं, मैं सभी धर्मों के प्रतीकों को जानता हूं, ये न्याय के लिए खड़े हैं और ईश्वर तो हृदय में वास करता है — हृदयं तिष्ठति — हर आदमी के हृदय में भगवान का वास है। तो जो भी न्यायवादी है, न्याय के बारे में सोचता है, वह हमेशा यह सोचेगा कि न्याय में मिलावट नहीं होनी चाहिए, न्याय बिल्कुल pure होना चाहिए, as pure as honey. Why is honey treated so pure? It has the quality of secularism. It is a collection from various flowers. It is not from one flower. That is why unity in diversity is always good and we have that in India. We will learn lessons and improve our system rather than rejecting or commenting upon it. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of Gram Nyayalayas at the grass-roots level for the purposes of providing access to justice to the citizens at their doorsteps and to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic or other disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

*The motion was adopted*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-byclause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 20 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 21 for consideration. There is one amendment (No.1) by Shri Matilal Sarkar. Are you moving the amendment?

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, the hon. Minister did not cover it in his reply. It is regarding clause 21(2). The complainant should also be allowed to avail the benefit of empanelled lawyers.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Let me tell you that the 'legal aid' means the provision for a counsel. He is entitled to avail this opportunity under the section 'legal aid' which says that all poor people, with an income below Rs. 20,000 per annum, shall have right to legal aid. The 'legal aid' is a component of this. So, it is already there. Please withdraw your amendment.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am not moving my amendment.

*Clause 21 was added to the Bill.*

*Clauses 22 to 28 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 29 for consideration. There is one amendment (No.2) by Shri Matilal Sarkar. Are you moving your amendment?

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, my appeal to the hon. Minister is that everyone should be allowed to represent his case in his mother tongue. Instead of 'State language' it should be 'mother tongue'.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Let me clarify. It will create difficulty. In some States, there are people whose mother tongue is not Bengali. We are a pluralistic society. "मदर टंग" पर तो झगड़ा हो सकता है। इसकी भाषा पश्चिमी बंगाल में बंगाली होगी, तमिलनाडु में तमिल होगी, इसमें कोई एतराज नहीं है।

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, there are other groups also.

SHRI H.R. BHARDWAJ: You are from Tripura. There are so many kinds of people in your State.

**श्री एस.एस. अहलुवालिया**: इनका कहना है कि there are 22 languages that are officially recognized, like, Bengali, Punjabi, Gujarati, Malyali, *etc.* But there are more than two thousand dialects that are spoken in our country. When you say that the pleader or the judge can articulate, the local dialect should be treated as the language of communication. That's the point.

SHRI H.R. BHARDWAJ: That is what the spirit is. These cases will be dealt with in the language of the party. It has very much been taken care of. This is a radical provision. Unless people conduct in their own language they can't understand. I cannot record the words 'mother tongue', but we will clarify.

SHRI MATILAL SARKAR: Okay, Sir, I am not moving my amendment.

*Clause 29 was added to the Bill.*

*Clauses 30 to 40 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up First Schedule for consideration. There is one amendment (No.3) by Shri Matilal Sarkar. Are you moving your amendment?

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, this is about maximum year of punishment. It should not exceed one year. That's my contention.

SHRI H.R. BHARDWAJ: We will look into it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is giving assurance that he will look into it.

SHRI MATILAL SARKAR: Okay, Sir, I am not moving my amendment.

*The First Schedule was added to the Bill.*

*The Second Schedule was added to the Bill.*

*The Clause1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of Gram Nyayalayas at the grass-roots level for the purposes of providing access to justice to the citizens at their doorsteps and to

ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic or other disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto be passed."

*The question was put and the motion was adopted*

———————

## MESSAGE FROM LOK SABHA

### The Unorganised Workers' Social Security Bill, 2008.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 17th December, 2008, agreed without any amendment to the Unorganised Workers' Social Security Bill, 2008, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd October, 2008."

———————

## STATEMENTS BY MINISTERS

### (i) Status of implementation of components of Bharat Nirman relating to Ministry of Rural Development; (ii) Status of implementation of Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS); (iii) Status of implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)

**ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह)**: उपसभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं:—

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति। [Placed in Library. *See* No. L.T. 10,001/08]

(ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) के कार्यान्वयन की स्थिति। [Placed in Library. *See* No. L.T. 10,002/08]

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन की स्थिति। [Placed in Library. *See* No. L.T. 9794/08]

### Revision of Pay Scales of Teachers in Universities and Colleges

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Sir, this august House has expressed its concern, from time to time for the need to strengthen the quality of higher education in the country. One of the critical factors affecting the quality of universities and institutions imparting higher education, is our inability to attract and retain young and talented persons to the teaching profession, leading over a period of time to shortage of teachers in central as well as state universities and other higher educational institutions. It is estimated that in Central Universities and constituent colleges